

CHOICE OF MILLIONS SINCE 1970
CHARMINAR®



BEST SELLER

www.charminarbrush.com

PAINT ROLLER

9440297101

खबरें जो सोच बदल दे

शुभ

लाभ

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

CHOICE OF MILLIONS®
SHERKOTTI



BEST SELLER

www.charminarbrush.com

HARDWARE & PAINT TOOLS

ABRASIVE WATER PAPER

9440297101

भारत और नेपाल के बीच बोया जा रहा सांस्कृतिक विभाजन का विष

घर भारत में... खेत नेपाल में... रिश्ते मुश्किल में पड़े!

भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक विभाजन का विष बोया जा रहा है। कोशिश है कि भारत और नेपाल के पौराणिक सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते बिखर जाएं। नेपाल-भारत सीमा पर सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां के निवासियों के खेत नेपाल में हैं। बिहार में तो अनगिनत घर ऐसे मिलेंगे जहां घर का एक हिस्सा भारत में तो दूसरा हिस्सा नेपाल में है। ऐसे में आपसी रिश्ते बेहद मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं। नेपाल में अड्डा बनाए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के गुर्गों, आतंकी संगठनों, कट्टर इस्लामिक तत्वों और बांग्लादेशियों एवं रोहिंय्या

घुसपैठियों के कारण नाक में दम हो चुका है। तस्करों के कारण दोनों देशों के बीच चुनौतियां पहले से रही हैं। अब नेपाल की बांग्लादेश जैसी हालत से हालत अत्यंत खराब हो रही है। नेपाल में चल रही ताजा

गई हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि सदियों पुराने रिश्तों का प्रतीक है। यहां रौटी-बेटी का बंधन है, सांस्कृतिक समानताएं हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आपसी जुड़ाव है। लेकिन ये रिश्ते अब नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तस्कारी, अपराध, घुसपैठ और यहां तक कि आतंकवाद की साजिशें इस खुली सीमा को खतरे में डाल रही हैं।

भारत और नेपाल के बीच की सीमा लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा पांच भारतीय राज्यों से गुजरती



संकट में संबंध

भारत

नेपाल

है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सिक्किम में यह 99 किमी, पश्चिम बंगाल में 100 किमी, बिहार में 729 किमी,

उत्तर प्रदेश में 560 किमी और उत्तराखंड में 263 किमी फैली हुई है। यह सीमा ज्यादातर खुली हुई है, यानि कोई दीवार या फेंसिंग नहीं है। दोनों देशों के

लोगों को आसानी से आने-जाने की आजादी है। कभी यह खुलापन आपसी रिश्ते के लिए जरूरी था, लेकिन अब यह खुलापन सुरक्षा के लिए सिरदर्द बन गया है। वर्ष 1815-16 के एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद 2 दिसंबर 1815 को हुई सुगौली संधि के जरिए नेपाल का एक-तिहाई हिस्सा ब्रिटिश भारत के हवाले कर दिया गया था, जिसमें तराई के ज्यादातर इलाके शामिल थे। संधि में काली नदी (महाकाली) को पश्चिमी सीमा के रूप में तय किया गया, जो आज भी विवाद का कारण है। संधि में तराई का बड़ा हिस्सा,

कुमाऊं-गढ़वाल, सिमला हिल्स, सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र शामिल थे, जो भारत की तरफ रहे। नेपाल की पश्चिमी सीमा को महाकाली नदी (काली

इस्लामी कट्टरपंथियों घुसपैठियों और तस्करों के कारण चुनौतियां गंभीर

इस संधि ने सीमा का बंटवारा किया, लेकिन इसमें कई खामियां थीं। नदियों के बदलते रास्ते और जंगलों ने सीमा को अस्पष्ट बना दिया। नतीजा ये हुआ कि कई गांव और खेत बंट गए। जैसे, एक तरफ घर भारत में तो खेत नेपाल में। ऐसे कई इलाके हैं जहां परिवार बंटे हुए हैं। उदाहरण के लिए सुस्ता और कालापानी जैसे क्षेत्र आज भी विवादित हैं, जहां नदी के बदलते बहाव ने सीमा को उलझा दिया है। संधि के समय ब्रिटिश अधिकारियों ने नक्शे बनाए, लेकिन वे सटीक नहीं थे।

नेपाल में अनियंत्रित हिंसा को काबू करने उतरी सेना

असम सरकार ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया

अब अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने की कवायद

10 दिन में साबित करनी होगी नागरिकता

काठमांडू, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

नेपाल में जारी अनियंत्रित हिंसा को काबू में करने के लिए आखिरकार सेना को मैदान में उतरना पड़ा। वैसे भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मंत्रियों के इस्तीफे से नेपाल में शासनिक-प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया था। सेना ने सम्पूर्ण नेपाल में कर्फ्यू लागू कर दिया है। नेपाली सेना के





प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने देश के नाम अपने संबोधन में प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर हिंसा, लूटपाट और आगजनी बंद नहीं हुई, तो सेना सख्त कार्रवाई करेगी। सेना प्रमुख ने कहा कि कुछ समूह इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और आम नागरिकों तथा

पीएम, राष्ट्रपति समेत पूरे शासन का इस्तीफा हिंसा में शामिल तत्वों पर संदेह, जेल भी तोड़ा

ही कहना है कि पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला करने का पाप नेपाल के युवक कैसे कर सकते हैं।

हिंसाग्रस्त नेपाल में नया कार्यकारी प्रधानमंत्री चुनने की कवायद भी शुरू हो गई है। पहले तो बालेन शाह का नाम चला लेकिन अब नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की के नाम को भारी समर्थन मिल रहा है। नेपाल की अस्थिरता के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और जरूरी हिदायतें दी हैं। नेपाल से खबर मिली है कि जेल तोड़ कर भागने

वाले कैदियों की संख्या छह हजार से अधिक है। यह नेपाल और पड़ोसी देश भारत के लिए अतिरिक्त सिरदर्दी साबित हो रहा है। कास्की जेल से सबसे ज्यादा 773 कैदी भागे हैं। वहीं चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी और जलेश्वर से 576 कैदी फरार हो गए हैं। इससे हिंसा और खतरनाक साबित हो सकती है। नेपाल के जलेश्वर से भागे 10 कैदियों

ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने पकड़ लिया।

प्रदर्शन के नाम पर फैलाई गई हिंसा में अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और देश के सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति भवन से लेकर तमाम सार्वजनिक संपत्तियां नष्ट हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदयविदारक है और इसमें कई युवाओं की जान गई है, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई है। उन्होंने नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए, सभी नेपाली भाई-बहनों से शांति बनाए रखने की विनम्र अपील की।

नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के चयन को लेकर हुई बैठक में शामिल पांच हजार से अधिक लोगों ने

गुवाहाटी, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

असम सरकार ने प्रदेश में नई मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर -एसओपी) जारी की है। इस एसओपी के मुताबिक किसी के संदिग्ध घुसपैठिया होने की दशा में उसे अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। इसमें असफल होने पर जिला प्रशासन 24 घंटे के भीतर उसके लिए डिपोर्टेशन का आदेश जारी कर देगा।

इस नए एसओपी से स्पष्ट है कि असम में घुसपैठिया होने के शक में पकड़े जाने पर अब सिर्फ 10 दिन में अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गुवाहाटी में असम कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि राज्य ने अब तक 30,128 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा है। इसके साथ ही असम सरकार ने एक नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू करने पर मुहर लगाई है। असम में घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए सरकार लगातार कमर कस कर काम कर रही है। ऑपरेशन पुशबैक समेत हर तरह से सरकार घुसपैठियों को राज्य और देश से बाहर निकालने पर काम कर रही है। इसी में अब राज्य में अवैध घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए। इन फैसलों का मूल उद्देश्य असम राज्य की

फेल हुए तो डिपोर्टेशन का आदेश जारी होगा

30,000 से अधिक घुसपैठिए बाहर किए गए

सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। बैठक में 1950 के प्रवासी निष्कासन अधिनियम के तहत एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) मंजूर किया गया। इसके तहत स्थानीय प्रशासन को सीधे कार्रवाई का अधिकार मिलेगा।

नए एसओपी पर सीएम सरमा ने कहा, अब हमें हर बार अदालत जाने की जरूरत नहीं है। जिला आयुक्त अब सीधे घुसपैठियों की पहचान कर डिपोर्टेशन या निष्कासन का आदेश जारी कर सकते हैं।

असम में लागू किए गए नए एसओपी के

अनुसार, यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध घुसपैठिया पाया जाता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 10 दिन में वह अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता तो जिला प्रशासन 24 घंटे के भीतर उसके लिए डिपोर्टेशन का आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद व्यक्ति को या तो होलिंग सेंटर में भेजा जाएगा या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की मदद से देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया अब विदेशी न्यायाधिकरणों को दरकिनार कर सीधे प्रशासनिक स्तर पर की जा

सकेगी।मुख्यमंत्री सरमा ने इस फैसले को ऐतिहासिक और निर्णायक बताया। उन्होंने कहा, हमारे न्यायाधिकरणों में 82,000 से अधिक मामले लंबित हैं और यह एसओपी उस प्रणाली को दरकिनार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एसओपी उन लोगों पर भी लागू होगा जिनका नाम एनआरसी में शामिल होने के बाद भी उनकी नागरिकता पर संदेह हो।

असम कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि सभी चिन्हित व्यक्तियों के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण को फॉरनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे भविष्य में निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति सीमा पार करते हुए 12 घंटे के भीतर पकड़ा जाता है, तो उसे बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस भेजा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा

हम अपने संविधान की वजह से सुरक्षित हैं

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने भारतीय संविधान की सराहना की और कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मुख्य

न्यायाधीश ने कहा, देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। हमने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। हमारा संविधान इस तरह बनाया गया है कि जिससे हमारा लोकतंत्र हमेशा सुरक्षित रहे।

जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस बात का समर्थन किया और बांग्लादेश के तनावपूर्ण माहौल का भी जिक्र किया। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान भारत की संवैधानिक स्थिरता को प्रमाणित करता है, जबकि पड़ोसी देशों में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, उसे दुनिया देख रही है।

कई बैंकों से की गई 346 करोड़ की धोखाधड़ी

दिवालिया कंपनी के मालिकों और दलालों ने किया फ्रॉड

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

346 करोड़ के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु और कर्नाटक में व्यापक छापामारी की। यह घोटाला बिजली क्षेत्र की कंपनी और उसके प्रवर्तकों की ओर से किया गया। गुरुग्राम स्थित हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), उसके निदेशकों अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्रोंई के अलावा कुछ अन्य के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। एचपीसीएल कंपनी खुद को दिवालिया भी घोषित कर चुकी है और उसके लिक्विडेशन की प्रक्रिया भी चल

रही है। दूसरी तरफ, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर भी सौ करोड़ से अधिक की अवैध सम्पत्ति मामले में ईडी ने कार्रवाई की है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी का मामला फरवरी 2025 में सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। प्रवर्तकों पर आरोप है कि उन्होंने ऋण राशि को अपनी कुछ संबद्ध संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया, जिससे बैंकों को नुकसान हुआ। ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने इस जांच के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित पांच परिसरों, चेन्नई में तीन और बेंगलुरु में एक परिसर की

काले धन से अय्याशी: कांग्रेस विधायक ईडी के शिकंजे में

तलाशी ली। शिकायतकर्ता बैंकों की ओर से घोषित कथित धोखाधड़ी की राशि 346.08 करोड़ रुपए है, जिसमें पीएनबी

165.71 करोड़ रुपए की ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि बैंक गारंटियों को वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में बदलने सहित कई पुनर्गठनों के बावजूद एचपीसीएल ने डिफॉल्ट किया और 31 मार्च, 2015 को इसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। बाद में 13 जून, 2024 को आरबीआई के पास इसके बतौर धोखाधड़ी के रूप में नामित करने की रिपोर्ट भेज दी गई।कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की की अवैध कमाई और सम्पत्तियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है।

10

सोनिया गांधी की तरफ से नहीं आया कोई वकील

नागरिकता के बिना वोटर लिस्ट में नाम कैसे?

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में शामिल होने वाले मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोनिया गांधी की ओर से कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हुआ। दिल्ली के राजज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि मतदाता बनने के लिए सबसे पहले भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक की सीमा पार करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लिया। नारांग ने 1982 में सोनिया गांधी का नाम हटाने के पीछे का कारण भी पूछा और कहा कि जरूर चुनाव आयोग को फर्जी दस्तावेज मिले होंगे तभी नाम हटाया गया। यह मामला सोनिया गांधी पर आपराधिक कार्रवाई करने की मांग से जुड़ा है। जब शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका



10



पाक के खैबर पख्तूनख्वा में सेना ने टीटीपी कमांडर अलीमुल को मार गिराया, 8,000 से ज्यादा आतंकी अभी भी मौजूद

इस्लामाबाद, 10 सितंबर (एजेंसियों)।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नु के जानी खेल इलाके में एक अभियान में प्रतिबंधित टीटीपी गुल बहादुर समूह के प्रमुख कमांडर को मार गिराया। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। इस बीच, सरकारी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 से अधिक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादी मौजूद हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान

अलीमुल हक के रूप में हुई है, जिसे जानी कमांडर मंसूर के नाम से भी जाना जाता है। वह सेना के खिलाफ हमलों का सीधा नेतृत्व कर रहा था। उसने हाल ही में तोची चेकपोस्ट को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। कमांडर मंसूर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत के पर ही मौत हो गई। द न्यूज़ इंटरनेशनल खबर के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने एक चिंताजनक खुलासा करते हुए कहा

है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 से ज्यादा टीटीपी के आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी पड़ोसी अफगानिस्तान से सीमा पार करके देश में घुस आए हैं और पेशावर, टैंक, डेरा इस्माइल खान, बन्नु, लक्की मरवत, स्वात, शांगला और अन्य जिलों में मौजूद हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने सीपीईसी रोड, डी खान-बन्नु रोड और टैंक में चौकियां बना रखी हैं। ये आतंकवादी आम लोगों में शरण लेते हैं और सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। यह

चिंताजनक खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब पड़ोसी अफगानिस्तान की सीमा से लगा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, बलूचिस्तान के साथ-साथ आतंकवादी घटनाओं का देश झेल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर की अध्यक्षता में आयोजित जिरगा में कबायली नेताओं ने अफगानिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ पर निराशा व्यक्त की है। कबोलाई नेताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अफगान सरकार के समक्ष घुसपैठ का मुद्दा उठाएं।

न्यूज़ ब्रीफ

रूस पर निर्भर हंगरी ने शेल से 10 साल का गैस समझौता किया



बुडापेस्ट। रूस से ऊर्जा आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर हंगरी ने ब्रिटेन की ऊर्जा कंपनी शेल के साथ 10 साल का नया गैस आपूर्ति समझौता किया है। हालांकि हंगरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम रूस से दूरी बनाने या रूसी गैस पर निर्भरता कम करने के लिए नहीं है। पश्चिमी साझेदार के साथ अब तक का सबसे बड़ा सौदा, लेकिन रूसी आपूर्ति बनी रहेगी मुख्य आधार हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने मिलान में एक गैस सम्मेलन के दौरान बताया कि यह अब तक का पश्चिमी साझेदार के साथ सबसे लंबी अवधि और सबसे बड़ी मात्रा का अनुबंध है। इस समझौते के तहत 2026 से शुरू होकर 10 वर्षों तक हंगरी को कुल दो अरब घनमीटर गैस की आपूर्ति होगी। इससे पहले, 2021 से 2027 तक सालाना 250 मिलियन घनमीटर गैस आपूर्ति का अनुबंध पहले से ही शेल के साथ था। सिज्जार्टो ने कहा कि यह नई आपूर्ति रूस से आयातित गैस की जगह नहीं लेगी। उनके अनुसार, हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मौजूदा स्रोतों और मार्गों को छोड़ना नहीं है, बल्कि नए स्रोत और मार्ग जोड़ना है। हंगरी ने रूस की गैजप्रॉम कंपनी के साथ 15 साल का समझौता पहले ही किया हुआ है, जिसके तहत सालाना 4.5 अरब घनमीटर गैस की आपूर्ति 2036 तक सुनिश्चित है। हाल के वर्षों में इस अनुबंध को अतिरिक्त आपूर्ति समझौतों से भी पूरक किया गया है। हंगरी की अधिकतर गैस आपूर्ति रूस से टर्कस्ट्रीम पाइपलाइन और उसकी बाल्कन स्ट्रीम विस्तार परियोजना के जरिये बुल्गारिया और सर्बिया से होकर आती है।

प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप कुछ हफ्तों में कर सकते हैं टैरिफ पर बात



वाशिंगटन (अमेरिका)। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा कि वह आने वाले हफ्तों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों नेता एक मुश्किल व्यापार विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंच पाएंगे। ट्रंप ने नौ सितंबर को सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी! वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन करने वाली ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोपीय संघ के नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं कि वे भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने में उनका साथ दें ताकि रूस से ऊर्जा खरीद के लिए इन देशों को दंडित किया जा सके। ट्रंप ने मंगलवार को हुई एक बैठक में यूरोपीय संघ के अधिकारियों से कहा कि अगर वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के साथ युद्धविराम वार्ता में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए भारत और चीन पर नए टैरिफ लगाते हैं, तो वह उनके साथ शामिल होने को तैयार हैं।

एक और जंग की आहट: इजरायल ने कतर पर कर दिया हमला, इस्लामिक देशों में हड़कंप



दोहा। इजरायल ने हमาส से लड़ते-लड़ते कतर पर भी हमला कर दिया है। इससे तमाम इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जाने लगी कि इसी तरह हमले होते रहे तो एक और जंग को रोक पाना कठिन हो जाएगा। लेबनान, गाजा, सीरिया में हमलों के बाद इजरायल ने अब कतर पर भी हमला बोल दिया है। यह वही कतर है, जहां हमाल से साथ उसकी मध्यस्थता वाली बैठक चल रही थी। लेकिन इजरायल ने जिस तरह से मंगलवार को ताबड़तोड़ हमले दोहा के अंदर घुसकर किए हैं, उसने मिडल ईस्ट में एक नई आग लगा दी है। पाकिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, युएई समेत कई मुसलमान देशों ने इन हमलों की निंदा की है और इसे पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरनाक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को गलत बताया है और कहा कि इसकी लोकेेशन ठीक नहीं थी।

नेपाल में चप्पे-चप्पे पर सेना, नियंत्रण संभाला, प्रदर्शनकारियों से होगी वार्ता

काठमांडू (नेपाल), 10 सितंबर (एजेंसियों)।

देश में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का (बुधवार) तीसरा दिन है। नेपाल की सेना ने हिंसा रोकने के लिए मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सेना ने कहा कि मुश्किल घड़ी का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। सेना ने अपील की है कि लोग ऐसी गतिविधियां बंद कर दें। नेपाल में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल की मौजूदगी में नेपाल सेना और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच औपचारिक बातचीत होनी है। हालांकि, अभी इसका समय तय नहीं किया गया है।

ओली का इस्तीफा, काठमांडू छोड़ा - सारे देश में चल रहे प्रदर्शन और लोगों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ दिया है। इससे पहले आंदोलनकारियों ने केपी ओली के निजी घर, राष्ट्रपति भवन और उच्चतम न्यायालय भवन को आग के हवाले कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है और 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने ओली को हेलिकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। उन्हें कहा ले जाया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। आंदोलनकारियों ने मंगलवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खलाना और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में आग लगा दी। पूर्व पीएम झालानाथ खलाना के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया। यही नहीं वृत्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया।

सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल मिले प्रदर्शनकारियों से - नेपाल में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल की मौजूदगी में नेपाल सेना और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच औपचारिक बातचीत होगी। हालांकि, अभी इसका समय तय नहीं किया गया है। मंगलवार रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में युवा प्रतिनिधियों और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल के बीच अनौपचारिक



बातचीत हुई है। इसके बाद सुबह से औपचारिक बातचीत की तैयारी की गई है।

नातचीत का एजेंडा - इस बातचीत का मुख्य एजेंडा नागरिक सरकार का गठन, संसद भंग करना और नए चुनाव कराना होगा। प्रदर्शनकारी युवा मांग कर रहे हैं कि पार्टियों को सत्ता से हटाकर जनता के नेतृत्व में नई सरकार बनाई जाए। काठमांडू महानगर के प्रमुख बालेन शाह ने भी संसद भंग करने की शर्त पर बात करने का समर्थन किया है। प्रदर्शन के चलते कई फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। खबर है कि चितवन जिले में प्रदर्शनकारियों ने रात को जिला प्रशासन कार्यालय और चुनाव कार्यालय में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी की बुधवार सुबह तक इसे नहीं बुझाया जा सका। पुलिस के अनुसार, जिला अदालत और सरकारी वकीलों के ऑफिस में भी आग लगाई गई, जिससे कई कागजात नष्ट हो गए। भारतपुर और दूसरे क्षेत्रों में नगरपालिका और वार्ड कार्यालयों पर भी हमला हुआ है। नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी सेंटर के कार्यालयों को भी आग के हवाले कर दिया गया है।

सेना कर रही काठमांडू में गश्त, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताई - सेना ने काठमांडू सहित प्रमुख शहरों में गश्त शुरू कर दी है। सेना ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से प्रदर्शन न करने और शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख ने नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों पर चिंता जताई है।

रूस के खिलाफ पोलैंड ने खोला मोर्चा, गिरा दिए रूसी ड्रोन



वारसॉ। रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग में पोलैंड ने भी मोर्चा खोल दिया है। पोलैंड ने कई रूसी ड्रोन्स को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले बुधवार की अहले सुबह पोलैंड ने नाटो देशों के साथ मिलकर अपने एफ-16 लड़ाकू विमानों को उतार दिया और राजधानी वारसॉ स्थित अपने मुख्य हवाई अड्डे समेत कुल चार एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। यूक्रेन के पश्चिम में स्थित इस देश ने यह कदम तब उठाया है, जब रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन की वायु सेना ने पोलैंड को चेतावनी दी थी कि रूसी ड्रोन्स अब यूक्रेन की सीमा पार कर पोलैंड में घुसने जा रही हैं। इस सूचना पर पोलैंड की वायु सेना ने आनकानन में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी और कुछ ही देर बाद रूसी ड्रोन मार गिराए। पोलिश वायु सेना ने कहा है कि बार-बार उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पिछले साढ़े तीन साल से रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से पड़ोसी देश भी परेशान हैं। इसी क्रम में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अब घोषणा की है कि एक दिन बाद यानी गुरुवार को पोलैंड बेलारूस के साथ लगी पूर्वी सीमा को बंद करने जा रहा है। दरअसल, पोलिश ससरकार बेलारूस में चल रहे रूसी सेना के आक्रामक सैन्य अभ्यास से चिंतित है।

माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों को अगले साल फरवरी से हफ्ते में तीन दिन कार्यालय से करना होगा काम

वाशिंगटन, 10 सितंबर (एजेंसियों)।

दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों को अगले साल से सप्ताह में कम से कम तीन दिन कार्यालय से ही काम करना होगा। इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 2026 में फरवरी से शुरू होगा। माइक्रोसॉफ्ट की कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एमी कोलमैन ने नौ सितंबर को लिखे ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से यह सूचना साझा की। माइक्रोसॉफ्ट के दुनियाभर में 2,20,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं।



एमी कोलमैन के अनुसार, इसकी शुरुआत वाशिंगटन के रेडमंड स्थित कंपनी के मुख्यालय के पास के कर्मचारियों से होगी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण महामारी के बाद घर से काम करने की व्यवस्था शुरू हुई थी। ब्लॉग के अनुसार, मुख्यालय के बाद अमेरिका के अन्य स्थानों और वैश्विक कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू की जाएगी। ब्लॉग में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय के 50 मील के दायरे में रहने वाले कर्मचारियों से फरवरी 2026 के अंत तक हफ्ते में तीन दिन ऑफिस में काम करने की उम्मीद थी जाएगी। कोलमैन ने कहा कि अमेरिका स्थित अन्य कार्यालयों के लिए समय-सीमा और निगरान जल्द ही घोषित किए जाएंगे। उन्होंने लिखा है, मुझे याद है कि 90 के दशक के अंत में मैं हमेशा ऑफिस में रहती थी। लैपटॉप नहीं होते थे। ज्यादातर हॉल के ठीक नीचे के लोगों के साथ काम करती थी। जैस-जैस तकनीक विकसित हुई हम ज्यादा खुले, ज्यादा वैश्विक होते

गए। उन तरीकों से विस्तार करने में सक्षम हुए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। फिर महामारी ने सब कुछ बदल दिया। इसने हमें काम के बारे में अलग तरह से सोचने, पहले से कहीं अधिक जुड़ने के लिए प्रेरित किया। माइक्रोसॉफ्ट की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एमी कोलमैन ने लिखा, कार्यपद्धति में बदलाव से हम पीछे नहीं जा रहे हैं। यह समय की मांग है। हमने जो कुछ भी सीखा है, उसका सर्वोत्तम लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। एआई युग में हम पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विश्वस्तरीय तकनीक का निर्माण कर रहे हैं जो लोगों के जीने और काम करने के तरीके और हर जगह संगठनों के संचालन के तरीके को बदल रही है। उन्होंने कहा कि साप्ताह में तीन दिन कार्यालय में करने की योजना लागू करने के यह प्रमुख कारक हैं। फरवरी के आखिर में पुगेट साउंड से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद अमेरिका के अन्य स्थानों पर इसे लागू किया जाएगा।

ट्रंप प्रशासन ने दवा कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कानूनी शिकंजा कसा

वाशिंगटन (अमेरिका), 10 सितंबर (एजेंसियों)।

अमेरिका में पहली बार ट्रंप प्रशासन ने दवा कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कानूनी शिकंजा कसा है। अमेरिका दुनिया भर के उन दो देशों में से एक है जो सीधे उपभोक्ता तक पहुंचने वाली दवाओं के विज्ञापनों की अनुमति देता है। दूसरा देश न्यूजीलैंड है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक जापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से दवा कंपनियों पर विज्ञापनों में पारदर्शिता कानूनों का पालन करने का दबाव डाला गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन इन कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 100 चेतानवी पत्र भेजेगा।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों ने मंगलवार सुबह पत्रकारों कहा कि लक्ष्य पहले से मौजूद कानूनों का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को दवाओं, खासकर संभावित जोखिम कारकों के बारे में पारदर्शी और सटीक जानकारी मिले। अधिकारियों ने उन दवाओं या उत्पादों की ओर इशारा किया जिनका प्रचार इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया साइटों पर होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर दवाओं के प्रचार पर किए गए कई अध्ययनों में पाया गया है कि अक्सर दी जाने वाली जानकारी डॉक्टर से बात करने पर मिलने वाली जानकारी से कमतर होती है। 2015 के एक अध्ययन में पाया गया कि केवल एक तिहाई पोस्ट में ही दवाओं के संभावित नुकसानों का जिक्र था। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, भ्रामक प्रभाव पैदा करने वाले



इन विज्ञापनों के बढ़ते प्रचलन, खासकर दुष्प्रभावों का उचित रूप से खुलासा न करने से व्यापक निराशा हुई है। ये विज्ञापन अब बिना उचित जानकारी के सोशल मीडिया पर छा गए हैं और ऑनलाइन फार्मसियों के विज्ञापन भी उन्हीं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिनका पालन कई दवा कंपनियां करती हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि इन नियमों को लागू करने से सोशल मीडिया पर अराजकता कम होगी और कंपनियां समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रशासन के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह राष्ट्रपति का सबसे साहसिक कदम है। हालांकि यह स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर के पदभार ग्रहण करने से पहले किए गए वादे से कम है। उन्होंने कहा था कि टीवी पर दवाओं के विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा। केनेडी ने चुनाव से पहले ट्रंप की एंकरेली में कहा था, मैं डोनाल्ड ट्रंप को पुरानी बीमारियों की महामारी को दूर करने के लिए टीवी पर दवाओं के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दूंगा।

फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कुक को हटाने के ट्रंप के फैसले पर संघीय न्यायाधीश ने अस्थायी रोक लगाई

वाशिंगटन (अमेरिका), 10 सितंबर (एजेंसियों)।

अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार देररात राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के लीसा कुक को फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से हटाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। कोलंबिया के अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश जिया एम. कॉब का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के लिए झटका है। इस फैसले से कुक को अपनी हालिया बर्खास्तगी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सेवा जारी रखने की अनुमति मिल गई।

रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कुक को उनके बंधक संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोपों के चलते बर्खास्त करने की कोशिश की थी। उन पर न तो कोई सीधा लिखित आरोप लगाया था और न ही उन्हें किसी अपराध का दोषी ठहराया गया था। कुक के वकीलों ने उन्हें पद से हटाने के प्रयास को राजनीति से प्रेरित बताया था।

यह फैसला राष्ट्रपति के किसी फेड अधिकारी को कारणवश हटाने की क्षमता को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई की पहली कड़ी है। कारणवश शाब्द का अर्थ आमतौर पर पेशेवर लापरवाही या गलत काम करना समझा जाता है। फैसले में न्यायाधीश कॉब ने कहा कि कुक को हटाने के



लिए ट्रंप द्वारा दिए गए तर्कों पर्याप्त कारण की सीमा को पूरा नहीं करते, क्योंकि यह कार्यवाही फेड गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल शुरू होने से पहले हुई थी। कुक ने बंधक दस्तावेजों पर 2021 में हस्ताक्षर किए थे। यह समय तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन के उन्हें नियुक्त किए जाने के बाद फेड में शामिल होने से लगभग एक साल पहले का था।

न्यायाधीश ने कहा, कारणवश प्रावधान का

सबसे अच्छा अर्थ यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के किसी सदस्य को हटाने का आधार गवर्नर के पद पर आचरण और उनके द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों का ईमानदारी और प्रभावी ढंग से पालन किए जाने तक सीमित है। इस प्रकार, कारणवश किसी व्यक्ति को केवल उसके पदभार ग्रहण करने से पहले किए गए आचरण के आधार पर हटाने की बात नहीं करता।

ए-वन स्टील्स और बीएसपीपीएल विवाद में सेबी और एमसीए से हस्तक्षेप की मांग

मूल कंपनी को बताए बगैर लीज़ कंपनी ने बैंक से लिया सौ करोड़ का ऋण

650 करोड़ जुटाने के लिए आईपीओ लाने की जुगाड़ में लगी लीज़ कंपनी

बैंगलुरु, 10 सितंबर।

बसई स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (बीएसपीपीएल) के निदेशकों में से एक के रविशंकर ने ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी के मामलों में कॉर्पोरेट प्रशासन के उल्लंघन, नियामक निरीक्षण और वित्तीय गलतबयानी के बारे में गंभीर चिंता जताई है।

रविशंकर ने कहा कि जिसे सद्भावना के आधार पर बसई स्टील्स के महत्वपूर्ण शेयरधारकों में से एक बनाया गया था, वही तमाम

अराजकताएं फैलाने में संलग्न है।

बसई स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने ड्राफ्ट रेफरी हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिए गए गलत बयानों के आरोप लगाए हैं। बसई स्टील्स के बेल्गारी प्लांट-1 के लीज़ डीड के कानूनी दस्तावेज़, पंजीकरण और प्रावधानों को ताक पर रख कर ए-वन स्टील्स ने नियोजित तरीके से भ्रामक स्थिति पैदा की। बेल्गारी प्लांट-1 कभी भी ए-वन स्टील्स के स्वामित्व में नहीं था, लेकिन डीअ-रपी में इसके विपरीत दर्शाया गया

है। ए-वन स्टील्स ने बसई स्टील्स की संपत्तियों को सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए का टर्म लोन ले लिया। इसके लिए महत्वपूर्ण शेयरधारकों और केनरा बैंक सहित प्रमुख हितधारकों को आवश्यक नोटिस और जानकारी न देकर कानून का सीधा उल्लंघन किया गया।

इसके अलावा, ए-वन स्टील्स के दबाव में बसई स्टील्स के तथाकथित प्रबंधन ने संचार के अनौपचारिक

साधनों का उपयोग करते हुए महज 55 मिनट का नोटिस देकर 07 अप्रैल 2025 को बोर्ड की बैठक आयोजित कर ली और उसमें पूंजी संरचना, लेखा परीक्षक परिवर्तन और कंपनी के नियंत्रण को प्रभावित करने वाले 16 एजेंडों पर निर्णय ले लिए गए। यह सचिवीय मानकों और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का आपराधिक उल्लंघन है।

बसई स्टील्स के निदेशक के. रविशंकर ने कहा, इस तरह तथ्यों को छिपा कर कंपनी की संपत्तियों

का दुरुपयोग किया गया और तमाम निवेशकों के साथ-साथ भारत के प्रतिभूति बाजार को भी गुमराह किया गया। लिहाजा, इस मामले में तत्काल नियामक हस्तक्षेप ज़रूरी है। रविशंकर ने मर्चेंट बैंकर प्रभुदास लीलाधर कैपिटल की नाकामी पर भी गहरी चिंता जताई है।

यह ध्यान देने योग्य है कि ए-वन स्टील्स ने प्रतिभूति बाजारों से 650 करोड़ रुपए जुटाने के लिए दिसंबर 2024 में सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया था। इसके बाद, सेबी

ने मई 2025 में बिना किसी अवलोकन के डीआरएचपी को मंजूरी दे दी।

विडंबना यह है कि जून और जुलाई 2025 में औपचारिक शिकायतें दर्ज होने के बावजूद, सेबी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे यह चिंता पैदा हो रही है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को स्वतंत्र जांच के बिना खारिज किया जा रहा है। हितधारकों का आरोप है कि मई 2025 में ए-वन स्टील्स के डीअ-रएचपी को सेबी द्वारा मंजूरी देते

समय संवेदनशील तथ्यों की अनदेखी की गई।

बसई स्टील्स में कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र की विफलता का मुद्दा भी एमसीए के समक्ष उठाया गया है। स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के बाद खुदरा निवेशकों को होने वाले नुकसान को देखते हुए, निवेशकों की सुरक्षा और भारत के पूंजी बाजारों में कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को बनाए रखने के लिए मजबूत नियामक सतर्कता की तत्काल आवश्यकता है।

मारवाड़ी युवा मंच पर्ल महिला शाखा द्वारा अन्नदान का आयोजन

हैदराबाद, 10 सितंबर
(शुभ लाभ ब्यूरो)।

मारवाड़ी युवा मंच पर्ल महिला शाखा ने श्राद्ध पक्ष के अवसर पर अन्नदान कार्यक्रम का हर्षोल्लासपूर्वक आयोजन किया। यह सेवा कार्य शाखा की अध्यक्ष शीतल जैन के नेतृत्व में लोअर टैकमेट स्थित गौशाला के बाहर सम्पन्न हुआ। शाखा मंत्री सुमन घोड़ेला द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी सदस्यों ने अपने-अपने घर से भोजन बनाकर लाया और लगभग 400 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। सभी की सक्रिय भागीदारी से यह कार्यक्रम



अत्यंत सफल रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व अध्यक्ष वर्षा मखाना, निवर्तमान अध्यक्ष रक्षा जैन, संरक्षक विना जैन, पुष्पा कोठारी, संतोषी गुजरानी, मीना दुग्गड़, वंदना दुग्गड़, सीता गांधी, चंदा मोदी, ज्योति मखाना, बबीता शर्मा, उर्मिला ढल्ला, माया सेन, दुर्गा मालवीया, मधु शर्मा, शिल्पा जोशी, आशा लुणावत, संतोष चौहान, शीला धोखा, सुनीता डूंगरवाल, हंसा कतरी, सीमा खीवसरा, सरोज पुडवाल, अंजू बाफना, ममता चौरडिया एवं पूनम मनोत का विशेष सहयोग रहा।

राजा सिंह ने किशन रेड्डी को दी चुनौती, कहा- मैं इस्तीफा नहीं दूंगा

हैदराबाद, 10 सितंबर
(शुभ लाभ ब्यूरो)।

गोशामहल के विधायक राजा सिंह ने एक बार फिर अपने बयानों से राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह इस्तीफा देते हैं तो वह भी इस्तीफा देने को तैयार हैं।

मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा, मैं विधायक पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर किशन रेड्डी इस्तीफा देते हैं, तो मैं भी दे



दूंगा। फिर हम दोनों निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। देखते हैं कि जनता किसे चुनती है। उन्होंने राज्य में भाजपा की मौजूदा स्थिति के लिए सीधे तौर पर किशन रेड्डी को जिम्मेदार

ठहराया। राजा सिंह ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव की भी आलोचना करते हुए उन्हें एक 'रबर स्टैप' बताया। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन चुनावों में उनकी जीत में पार्टी का कोई समर्थन नहीं था, बल्कि यह

गोशामहल की जनता का फैसला था।

राजा सिंह ने चेतावनी दी कि जब तक वर्तमान समिति सत्ता में है, भाजपा राज्य में दोबारा सत्ता हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर पार्टी किसी तरह सत्ता में आती है, तो वह राजनीतिक संन्यास लेने पर विचार कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह भाजपा नेता बने रहेंगे और उनका बीआरएस या कांग्रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कुछ पार्टी नेताओं पर पद खोने के डर से चुप रहने का आरोप भी लगाया।

मोदी और मेलोनी ने व्यापार समझौते और यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत की



नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को जल्द संपन्न कराने में इटली के सहयोग तथा यूक्रेन में संघर्ष के जल्द समाधान के बारे में चर्चा की। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रीमती मेल-ोनी ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के लिए इटली के समर्थन को दोहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई तथा यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में सझा रुचि दिखाई। पास्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने और भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप गलियारे की पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया।

दिल्ली दंगा मामले में खालिद ने जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (एनएचयू) के पूर्व छात्र उमर खलिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत नहीं देने के आदेश को बुधवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

नीतीश कुमार ईमानदार पर इर्द-गिर्द के कई मंत्री और अफसर भ्रष्ट: प्रशांत किशोर

बेगूसराय, 10 सितंबर
(एजेंसियां)।

बिहार के बेगूसराय में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में दो दिनों से लाठीचार्ज पर कहा कि जो लाठी चार्ज करवा रहे हैं उनके पार्टी के नेता आपके गांव वोट मांगने जाएं तो उन्हें लाठी मारे या न मारे लेकिन उन्हें खदेड़ने का काम जरूर करें। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं लेकिन उनके इर्द-गिर्द के पांच मंत्री और पांच अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में मकान खरीद रहे हैं। उन्हें जनसुराज का राज आने पर जेल भेजने का काम किया जाएगा।

दरअसल प्रशांत किशोर बुधवार को बखवारा विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बिहार बदलाव यात्रा पर पहुंचे थे। सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता और युवा जब तक अपने



अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे, जाति-धर्म के नाम पर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू को वोट देते रहेंगे, तब तक बच्चों पर लाठी चलती रहेगी। बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस सरकार ने आपके बच्चों पर लाठी चलाया है, जब उसके नेता गांव आते हैं तो उस पर लाठी चलाइए या न चलाइए, उसको गांव से दौड़ा कर भगाइए। जिस तरीके से बच्चों को दौड़ाया गया, उसी तरह से नेता को दौड़ाइए।

प्रशांत किशोर ने कहा कि बड़े नेता और अफसर को चिह्नित

गरीबों में जी रहे हैं और वो यहां से पैसा लूटकर ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड में घर खरीद रहा है।

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं हैं, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मनमोहन सिंह भी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार थे, लेकिन यूपीए की उनकी सरकार को भ्रष्टाचार के लिए पूरे देश की जनता जानती है।

बिहार में जो चार भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी हैं, चारों का नंबर एक साथ आ रहा है। भाजपा में दम है तो इसी मैदान पर आकर सभा कर लें पता चल जाएगा कि कौन फेसबुक और सोशल मीडिया का नेता है और कौन जमीनी नेता जाना जाता है। पप्पू यादव की ओर से गाली के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसका जो संस्कार है वही करेगा। बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है, देश और राज्य में जो क्रांति हुई उसकी आवाज बेगू-सराय से गूंजी है।

नेपाल को लेकर बिहार के सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा पर बैठक

पटना, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

नेपाल में हाल ही में हुए 'नशप न' द्वारा आंदोलन और जेल तोड़कर भागने की घटनाओं के मद्देनजर, बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। आज दिनांक 10 सितंबर, 2025 को बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल की सीमा से सटे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नेपाल की हालिया घटनाओं



से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना था। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सीमा पार से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। किसी भी व्यक्ति को गहन जांच के बिना सीमा में प्रवेश न

करने देने का सख्त आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव ने राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों और महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट आदि पर भी कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा, ताकि किसी भी अग्रिय घटना को रोका जा सके। बैठक के दौरान, श्री प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को आश्वासित किया कि किसी भी तरह की आपात

स्थिति या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर वे सीधे उनसे या पुलिस महानिदेशक (उम्रझ) से संपर्क कर सकते हैं। यह निर्देश अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने और किसी भी परिस्थिति में देरी से बचने में मदद करेगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन भी उपस्थित थे। इसके अलावा, गृह विभाग के वरीय पदाधिकारी गण, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक इस बैठक से जुड़े थे।

एफटीए में घरेलू उद्योगों के हित के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शर्त शामिल की जायेगी: गोयल

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि विभिन्न देशों से साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर जारी वार्ताओं में भारत की ओर से घरेलू उद्योगों के संरक्षण के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री गोयल ने यहां वाहन डीलरों के महासंघ (फाडा) के सातवें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुये कहा, "हम कई विकसित देशों के साथ एफटीए पर बात कर रहे हैं। भारतीय बाजार के बड़े आकार को देखते हुये कई कंपनियां भी यहां निवेश कर रही हैं। हम निश्चित रूप से घरेलू उद्योगों और घरेलू विनिर्माताओं की सुरक्षा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, मेरी राय है कि हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी शामिल करेंगे।"

चुनाव आयोग ने लिया देशभर में एसआईआर शुरू करने की तैयारियों का जायजा

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

बिहार की तरह देश भर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू करने की दिशा में बुधवार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में दिन भर चली इस बैठक का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। बैठक में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी शामिल थे। राज्यों के सीईओ का राजधानी में इस साल आयोजित होने वाला यह तीसरा सम्मेलन था। जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ मौजूद थे।

एससीओ की क्षेत्रीय परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्र प्रमुखों के बाद उसकी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद (आरएटीएस) की बैठक में भी पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गयी है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि किर्गिजस्तान के चोलपोन अता में परिषद की 44 वीं बैठक आज हुई। बैठक में सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। परिषद ने एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की तिर्थांजिन में एक सितम्बर को हुई बैठक के बाद पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने वाले घोषणा पत्र का भी समर्थन किया। तिर्थांजिन में हुए शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। किर्गिजस्तान की अध्यक्षता में हुई आरएटीएस परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन ने किया। उन्होंने बर्बर पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रायोजकों, आयोजकों और वित्तपोषकों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उन्होंने सदस्य देशों का आह्वान किया कि सभी को आतंकवाद पर दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे तथा सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लेना होगा।

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज

कोर्टरूम ड्रामा में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी



बॉ लीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार ने इस ट्रेलर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म में एक बार फिर कोर्टरूम ड्रामा, सामाजिक मुद्दे, और हास्य का मेल देखने को मिलेगा।

इस बार कहानी और भी गंभीर और संवेदनशील विषय को उठाती नजर आती है, जिसमें दो जॉली, अक्षय कुमार और अरशद वारसी, आमने-सामने हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक गंभीर और भावनात्मक

डायलॉग से होती है, मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत में मिली, वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। इस वॉयसओवर के साथ दंगों, पुलिस के लाठीचार्ज और सामाजिक उथल-पुथल के दृश्य सामने आते हैं। इसी दौरान एक महिला 'स्वर्गीय राजाराम सोलंकी' की मूर्ति के पैरों से लिपटी दिखाई देती है।

इसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जो स्कूटर चलाते नजर आते हैं। वह पैसों के बदले में अपने अस्तिर से कहते हैं, कोई जॉली बोले तो उसे मेरे पास ही लेकर आना। अक्षय कुमार के साथ हुमा कुरैशी भी नजर आई हैं, जिनकी शराब पीने की

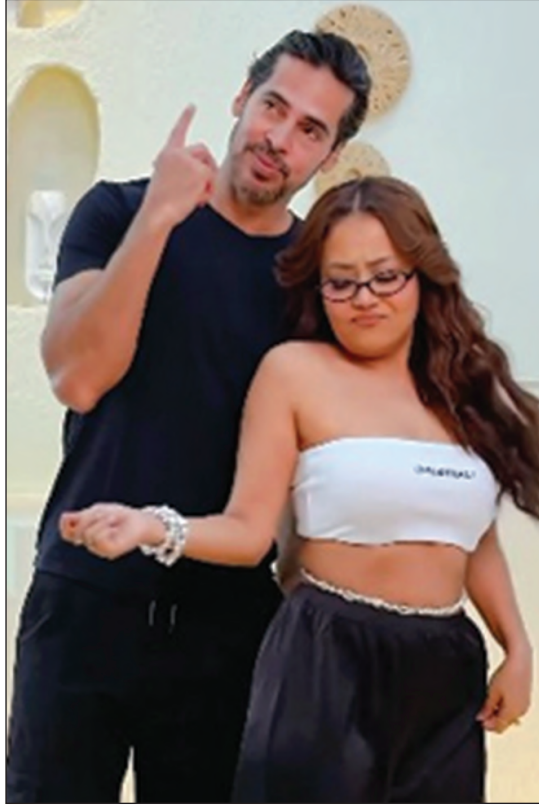
आदत से अक्षय परेशान दिखाई देते हैं। वहीं, अरशद वारसी एक बार फिर वकील के किरदार में हैं, जो खुद को बेहद बिजी बताते हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई काम नहीं होता। ट्रेलर में अक्षय और अरशद एक ही क्लाइंट को लेकर भिड़ते भी दिखते हैं। अरशद अक्षय को 'क्लाइंट चोर' तक कह देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है।

यह सीन दर्शकों को फिल्म के पहले भाग की याद दिलाता है। फिल्म की कहानी में एक जमीन विवाद को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है, जिसमें खेतान साहब, जिनका किरदार गजराज राव निभा रहे हैं, एक प्रभावशाली भूमिका में दिखाई देते हैं।

अक्षय कुमार खेतान साहब से मिलने के लिए किसी से गुजारिश करते हैं, जो कहता है कि उन्हें खुद मिलने में एक साल और नाम याद कराने में दो साल लगे। लेकिन, चौंकाने वाला मोड़ तब आता है, जब खेतान साहब खुद अक्षय से मिलने पहुंचते हैं। इस केस को लेकर अक्षय और अरशद एक बार फिर आमने-सामने आते हैं। कोर्टरूम में दोनों वकीलों के बीच की बहस, रणनीति और नोकझोंक कहानी को दिलचस्प मोड़ देती है।

ट्रेलर में अमृता राव की झलक भी देखने को मिली है। ट्रेलर से साफ है कि 'जॉली एलएलबी 3' कॉमेडी के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर गंभीरता से सवाल उठाएगा। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नेहा कक्कड़ और डिनो मोरिया का तू प्यासा है, मैं पानी सनम में शानदार डांस



म शहूर सिंगर नेहा का हाल ही में डिनो मोरिया के साथ गाना 'तू प्यासा है, मैं पानी सनम' रिलीज हुआ था। अब गायिका ने गाने पर वीडियो बनाई है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में नेहा और डिनो की जोड़ी गाने के बोल पर धमाकेदार डांस

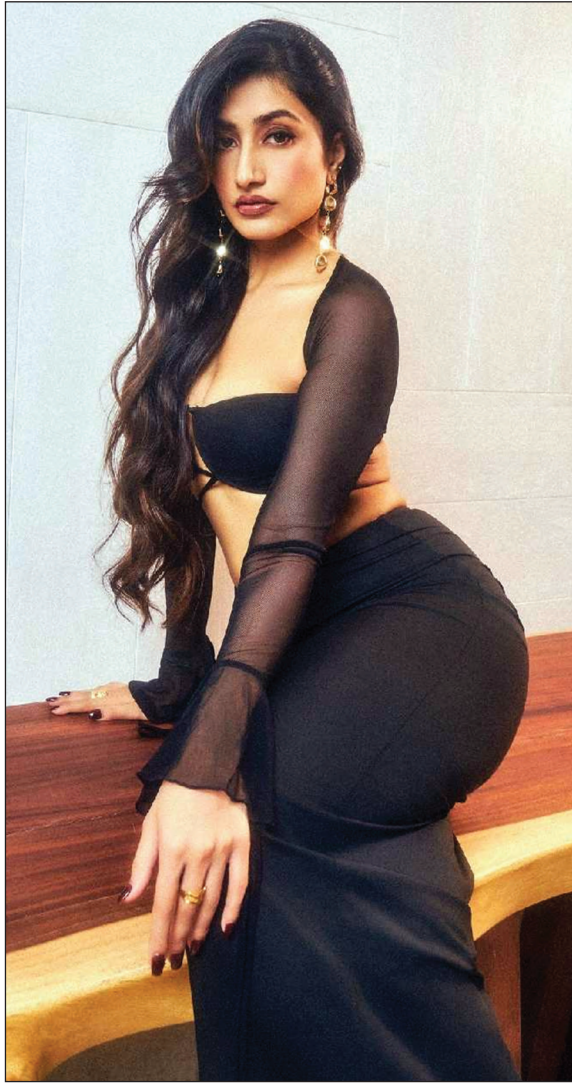
मूव्स करती नजर आ रही है।

वीडियो की शुरुआत में नेहा डिनो को डांस के लिए उकसाती हैं और खुद शानदार डांस मूव्स करने लगती हैं। उनके एनर्जेटिक मूव्स देखकर डिनो भी खुद को रोक नहीं पाते और नेहा के साथ कदम मिलाते हुए डांस करने लगते हैं। दोनों की केमिस्ट्री और डांस मूव्स ने फैंस का दिल जीत लिया है।

इस वीडियो में भी नेहा का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज छाया हुआ है, जबकि डिनो का स्टायलिश लुक गाने की रौनक को बढ़ा रहा है। लुक की बात करें तो नेहा ने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक पैंट पहना है, जो उनके स्टायलिश और ट्रेंडी अवतार को बखूबी दर्शाता है। वहीं, डिनो ने ब्लैक शर्ट और पैंट में अपना क्लासिक चार्म बिखेरा है। नेहा ने वीडियो के कैप्शन में कुछ नहीं लिखा, बस दो ब्लैक एंड व्हाइट इमोजी डाले, जो उनके और डिनो के लुक के साथ परफेक्टली मेल खाते हैं। 'तू प्यासा है, मैं पानी सनम' एक रोमांटिक और एनर्जेटिक गाना है, जिसमें नेहा का सिज़लिंग अवतार देखने लायक है। गाने का म्यूजिक और बीट्स युवाओं को खूब पसंद आ रहा है। डिनो मोरिया की मौजूदगी ने गाने को और भी आकर्षक बना दिया है। इस गाने को यूट्यूब और अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है और इसे अब तक 5.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। टोनी कक्कड़ ने गाने को लिखने के साथ-साथ

संगीतबद्ध भी किया है। इस गाने को आदिल शेख ने डायरेक्ट किया है। इसकी कोरियोग्राफी मोहित और सेरेन ने की है।

युजवेंद्र चहल से तलाक नहीं, टैलेंट की वजह से मिल रहे हैं फिल्मों के ऑफर: धनश्री



को रियोग्राफर और अभिनेत्री इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं। उन्हें इस शो के अलावा भी कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि इसकी वजह युजवेंद्र चहल से उनका तलाक है, वह इसके लिए

खूब सुखियों में रहीं।

धनश्री वर्मा तलाक से मिली लोकप्रियता को भुना रही है, इस पर अब उनका रिएक्शन सामने आया है। धनश्री वर्मा ने बताया कि फिल्मों के ढेर सारे ऑफर मिलना तलाक की वजह से नहीं, बल्कि उनका टैलेंट है। धनश्री वर्मा ने कहा, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। मैं यहां अकेले खड़ी हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे काम मिल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे इंडस्ट्री से प्यार है, क्योंकि लोग अब भी मुझे काम दे रहे हैं। मुझे ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि जो मेरे साथ हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझमें टैलेंट है। इसका किसी और चीज से कोई लेना-देना नहीं है।

धनश्री और चहल ने 2020 में सगाई की और उसी साल दिसंबर में दोनों ने गुरुग्राम में शादी कर ली थी, जिसमें उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी के पांच साल बाद फरवरी 2025 को दोनों का तलाक हो गया था। दोनों के तलाक ने खूब सुखियां बटोरी थीं। चहल के फैंस ने धनश्री को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया था।

धनश्री वर्मा ने फिल्म 'भूल चूक माफ' के गाने 'टिंग लिंग सजना' से बड़े पर्दे पर धूम मचा दी थी। इसमें वो अभिनेता राजकुमार राव के साथ नजर आई थीं। इसके अलावा, वह वीडियो सांगा 'देखा जी देखा मैंने' में भी दिखाई दी थीं। बहुत जल्द धनश्री वर्मा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दिल राजू की फिल्म 'आकाशम दाती वस्तावा' में दिखाई देंगी। यह उनका तेलुगु डेब्यू होगा। फिल्म की कहानी डांस पर आधारित है। इन दिनों वो रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में सभी कंटेस्टेंट को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं।

अभिनेत्री वाहबिज दोराबजी ने तनाव की वजह से बीच में छोड़ा था सीरियल

टी वी एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी को 'प्यार की एक कहानी', 'सरस्वती चंद्र', और 'बहु हमारी रजनीकांत' जैसे सीरियल्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के मुश्किल दौर को याद किया। साथ ही बताया कि कैसे काम के तनाव की वजह से उन्हें एक सीरियल को बीच में ही छोड़ना पड़ गया था।

वाहबिज ने कहा, हां, मैंने एक शो बीच में ही छोड़ दिया था। मेरे जाने के कुछ दिनों बाद वो शो बंद हो गया क्योंकि शो उन पर ही आधारित था। सच कहूं तो काम के तनाव ने मुझ पर बहुत बुरा असर डाला था। मुझे मधुमेह था और ये गंभीर स्थिति तक पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने मुझे आराम करने की सलाह दी थी। इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था।

अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, मैं खुद पर, अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। रिश्तों के मामले में मैं बहुत पुराने जमाने की हूँ। मैं 90 के दशक के प्यार में विश्वास करती हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती हूँ जो मेरे जीवन में कुछ अर्थ जोड़े, जो मेरे बराबर का हो, महत्वाकांक्षी हो, फिर भी परिवार के प्रति समर्पित हो। मुझे आजकल के स्वाइप कल्चर से बहुत डर लगता है। टीवी इंडस्ट्री के बिजी शेड्यूल पर भी उन्होंने बात की। वाहबिज दोराबजी ने अपनी राय रखते हुए कहा, टेलीविजन बहुत ही डिमांडिंग इंडस्ट्री है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। कभी-कभी प्रसारण का दबाव होता है और आप अपने प्रोडक्शन को कम नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर इतना दबाव नहीं झेल पाता। मेरा मानना है कि आज की दुनिया को एक संतुलित और समग्र जीवनशैली की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर काम का समय सीमित कर दिया जाए, तो कलाकारों के अभिनय में निखार आएगा, वे स्वस्थ रहेंगे, और उत्पादकता भी बढ़ेगी। इससे सबको फायदा होगा।

मैं सुरक्षित हूं : काजल अग्रवाल मौत की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी



सा उथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी और बेहतरीन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में एक चौंकाने वाली

अफवाह फैलने लगी। कई जगहों पर यह दावा किया गया कि काजल अग्रवाल का एक सड़क हादसे में निधन हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया

कि वह गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक है। इन खबरों के चलते फैंस चिंता में आ गए। हर कोई उनकी सलामती को लेकर परेशान हो गया। लेकिन, अब खुद काजल ने इन तमाम झूठी बातों का जवाब दिया है और बताया है कि वह बिल्कुल ठीक हैं। काजल अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट में साफ किया कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि वह किसी हादसे में मर चुकी हैं। काजल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये खबरें न सिर्फ फर्जी हैं, बल्कि काफी मजेदार भी हैं, क्योंकि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान की कृपा से वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अच्छी जिंदगी जी रही हैं। काजल ने अपने फैंस से विनम्र निवेदन करते हुए कहा, 'कृपया इस तरह की झूठी बातों पर विश्वास न करें और न ही इन्हें आगे बढ़ाएं। हमें निगेटिव चीजों से हटकर पॉजिटिव और सच्ची बातों पर ध्यान देना चाहिए।' इस बयान के बाद उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली और सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारा प्यार भेजा।

वर्कफ्रंट

की बात करें तो काजल अग्रवाल पिछली बार एक्टर विष्णु मांचू की फिल्म 'कन्नप्पा' में नजर आई थीं। उनकी झोली में मशहूर डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' भी है। इस पौराणिक फिल्म में वह रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा, उनके पास 'द इंडिया स्टोरी' और 'इंडियन 3' जैसी फिल्में भी हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी और बेहतरीन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में एक चौंकाने वाली अफवाह फैलने लगी। कई जगहों पर यह दावा किया गया कि काजल अग्रवाल का एक सड़क हादसे में निधन हो गया है।

ट्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल, 17 सितंबर 2025 को बुधवार के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले पूजे जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा के साथ गणेश जी का अशीर्वाद मिलने से यह दिन और भी शुभ हो जाता है। अगर आप नया दोपहिया या चौपहिया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस दिन वाहन की डिलीवरी लेना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सफलता और सुरक्षा का प्रतीक भी बन सकता है।

सम्पादकीय

गुरुवार, 11 सितंबर, 2025

हैदराबाद

शुभ लाभ

खबरें जो सोच बदल दे

विजय शर्मा

संपादकीय

नेपाल में ‘जेन-जेड’ विद्रोह

नेपाल

मैं जेनरेशन जेड के युवा आक्रोशित, आंदोलित और कुछ हद तक हिंसक होकर सड़कों पर होी नहीं, बल्कि संसद भवन के भीतर भी घुस गए थे। यह बगावत सोशल मीडिया पर थोपी गई पाबंदियों के महेनजर नहीं, बल्कि देश की ‘म्यूजिकल चेयर सत्ताओं’ के खिलाफ एक जन-विद्रोह है। देर रात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने फेसबुक, व्हाट्स एप, एक्स, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि 26 ऐप्स को पाबंदियों से मुक्त कर दिया, कई जगह कर्फ्यू भी उठा लिए गए, लेकिन जेन-जेड के युवा अब भी आंदोलित हैं। वे प्रधानमंत्री ओली की सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह पीढ़ीगत फासलों और संक्रमण की लड़ाई है, द्वंद्व है। युवा देश में अपने प्रतिनिधित्व की सरकार चाहते हैं, ताकि उनकी तकलीफों को समझा जा सके। युवाओं का पलायन रोक जा सके। पढ़ाई और नौकरी के लिए उन्हें विदेशों में धक्के न खाने पड़े। समग्रता में युवाओं का यह विद्रोह बेरोजगारी, महंगाई, व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्हें अब न तो प्रचंड का नेतृत्व चाहिए और न ही उन्हें ओली स्वीकार्य हैं। यह विद्रोह

नेपाल में सत्ता-परिवर्तन की नई प्रस्तावना लिख सकता है। नेपाल में लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति भी जेन-जेड का मोहभंग इतना गहरा हो गया है कि वे राजशाही की बहाली के पक्ष में भी आंदोलित रहे हैं। बहरहाल नेपाल में अचानक उग्र हुए युवा विद्रोह में 20 मौतें हो चुकी हैं और करीब 500 युवा घायल हैं। पत्रकारों को भी गोली लगी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। विद्रोह के कारण राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के आसपास कर्फ्यू लगाया पड़ा था। सुरक्षा बंदनी पड़ी थी। कर्फ्यू 7 शहरों में लगाया गया था। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई और गृहमंत्री रमेश लेखक ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। दरअसल नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि सोशल मीडिया की सभी विदेशी कंपनियां सरकार के आदेश का अनुपालन करें और नेपाल में ‘टिकटकों’ को छोड़ कर अन्य 26 ऐप्स को पंजीकरण करा स्थानीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति करें।

सोशल मीडिया जरूर देखते हैं। सभी प्लेटफॉर्म निशुल्क हैं। ऐसे में जेन-जेड के युवाओं को लगा मानो उनकी आवाज दबा दी गई हो! नेपाल में बेरोजगारी 10.71 फीसदी है। महंगाई 5.2 फीसदी है। आर्थिक असमानता इतनी है कि 20 फीसदी लोगों के पास 56 फीसदी संपत्ति है। भाई-भतीजावाद और चहेतों को कुर्सी पर बिठाने से नेताओं के बच्चों की विदेशी यात्राएं, ब्रांडेड सामान, शान-ओ-शौकत की पार्टियां सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगीं। फिलीपींस, इंडोनेशिया का ‘नेपो बेबी’ अभियान नेपाल में ही ट्रेण्ड करने लगा। सरकार ने पाबंदियां लगाईं, तो जेन-जेड ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश माना। बीते चार साल में तीन बड़े घोटाले सामने आए। करीब 55,000 करोड़ रुपए का ‘गिरी बंधु भूमि घोटाला’, करीब 14,000 करोड़ का ‘ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला’ और करीब 70,000 करोड़ रुपए का ‘सहकारिता घोटाला’ के अलावा बीजा, टेलीकॉम, पोखरा एयरपोर्ट आदि घोटाले भी चर्चा में रहे हैं। इनसे युवाओं का आक्रोश बढ़ता गया है। नेपाल के इस युवा विद्रोह पर अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस सरोखे पश्चिमी देशों ने भी चर्चित सरोकार जताया है और मुक्तकों के पर्तजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। हमारा ‘रोटी-बेटी’ का रिश्ता है। हमारे कई राज्यों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। नेपाली नौजवान पढ़ने और छोटी-मोटी नौकरी करने भी भारत में आते हैं। अनुमान है कि करीब 50,000 नेपाली युवा भारत में आते-जाते रहते हैं। जो नेपाली युवा विदेशों में काम करते हैं और घर को पैसा भेजते हैं, वह नेपाल की जींजीपी का करीब 25 फीसदी है। सोचिए, नेपाली युवाओं की यह बगावत सत्ता के बुढ़ों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। नेपाल भारत पर इतना आक्रांश्रुत है कि यदि हमारी सरकार मदद करना बंद कर दे, तो नेपाल त्राहिमाम करने लगेगा। बहरहाल आंदोलन अभी थमता नहीं लगता, क्योंकि जेन-जेड की मांग परिस्थितियों में बदलाव की है। अंततः प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा भी दे दिया है।

कुछ अलगा

घड़ियाली शुभाकांक्षी दिनों बाद...

पानी

पानी जिंदगी में दरवाजे पर रोज की तरह ये समय पानी लेकर दूधवाले के आने का होता है। पानी में दूध हो या न। पानी में दूध की शिकायत पर उसके पास हर रोज कोई न कोई नया लॉजिक उपलब्ध रहता है। शिकायतों की सीरीज में जैसे ही बीते कल फिर मैंने पतली में पानी में मिला दूध लेते शिकायत की थी कि यार! पानी में ही आज भी दूध है तो उसने लॉजिक देते पूरे काफिंडेस से कहा था, ‘अब रोज रोज क्या कहूं जनाब! आप तो जानते ही हैं कि दिन रात पानी बरस रहा है। गाय को किताब की छप्पर के नीचे बांध कर रखो पानी छप्पर से उस पर टपक ही जाता है। और वही पानी दूध में आ जाता है। मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि गाय पर बरसात का पानी न पड़े और सबको दूध ही दूध दूं, पर अब इसमें मेरा क्या दोष! ऊपर वाले से आपकी पहचान हो तो प्लीज! उससे बात कीजिएगा किता...!’ बंधुओं! स्मार्ट आदमी के पास और कुछ हो या न, पर अपनी बदतमीजी को छुपाने के लिए कोई न कोई लॉजिक हर समय उपलब्ध रहता है। लॉजिक इलॉजिकल हो तो होता रहे। पर दरवाजा खोला तो दूधवाले के बदले सामने बड़े दिनों बाद दिखा बेगाना सा लगता मुस्कुरात हुआ एक चेहरा। मैं उसको बड़ी देर तक पहचानने की कोशिश करता रहा। कभी इस एंगिल से तो कभी उस एंगिल से उसका चेहरा ताकता रहा तो उसने ही अपना परिचय देते कहा, ‘बंधु! मैं सूरज! कैसे हो? सब कुशल मंगल है न !’ ‘सो तो ठीक है, पर कौन सूरज?’ मैं पूछता हुआ सिर में बाल न होने के बाद भी सिर के बालों के बीच खारिश करता रहा।

दृष्टि

कोण

क्यों हुई बाढ़ से इतनी तबाही?

देश के अनेक राज्य पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इस बार पंजाब और हिमाचल में आई बाढ़ ने इन्हें आर्थिक तौर पर काफी पीछे धकेल दिया है। इसे पिछले कई सालों की सबसे भीषण बाढ़ माना जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अत्यंत कम सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। सड़कों, पुलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। भारत में बाढ़, एक बार-बार आने वाली घटना रही है और इससे जान-माल, आजीविका प्रणालियों, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं को भारी नुकसान होता है। भारत की उच्च जोखिम संवेदनशीलता इस तथ्य से उजागर होती है कि 3290 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ की चपेट में है, जो कि 12

फीसदी है। राज्यवार अध्ययन से पता चलता है कि देश में बाढ़ से होने वाली क्षति का लगभग 27 प्रतिशत बिहार में, 33 फीसदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और 15 फीसदी पंजाब और हरियाणा में होता है। हिमाचल प्रदेश में भी इस बार बाढ़ और बारिश ने भारी नुकसान किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव जीवन और उद्योगों को क्षति पहुंची है। वन उद्योग के अलावा होटल और पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ के दौरान पानी में बहते लकड़ी के लंों के वीडियो का संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवंई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर बताया हुए कहा, ‘हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूखलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्ट्स से यह भी सामने आया कि बाढ़ के

1990 के दशक में भारत ने उदारीकरण की राह पकड़ी और चीन पहले से ही वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था

निवेश का नया दौर : भारत और चीन के बीच संभावनाओं की दिशा

शम्भू शरण सत्यार्थी

आज

लंबे समय तक आर्थिक विकास नहीं कर सकता। संसाधन कहीं और हैं, तकनीक कहीं और है और बाजार कहीं और। इस आपसी निर्भरता में वैश्विक निवेश और साझेदारी को मजबूरी ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी बना दिया है। भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, इसी प्रक्रिया का एक बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में जब चीन की 200 से अधिक कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई तो इस खबर ने आर्थिक गलियारों से लेकर राजनीतिक मंचों तक गहरी हलचल पैदा कर दी। यह महज पूंजी का मामला नहीं है बल्कि इसमें भविष्य की दिशा, भू-राजनीति और आत्मनिर्भरता का सवाल भी छिपा है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताएँ रही हैं और व्यापारिक दृष्टि से एक-दूसरे के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। रेशम मार्ग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने न केवल राजनीतिक मंचों तक गहरी हलचल पैदा कर दी। यह महज पूँजी का मामला नहीं है बल्कि इसमें भविष्य की दिशा, भू-राजनीति और आत्मनिर्भरता का सवाल भी छिपा है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताएँ रही हैं और व्यापारिक दृष्टि से एक–दूसरे के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। रेशम मार्ग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने न केवल वस्तुओं बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान–प्रदान करवाया किंतु आधुनिक काल में जब 1962 का युद्ध हुआ, तो दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। इसके बावजूद आर्थिक वास्तविकताओं ने धीरे-धीरे इस दीवार में दरारें डालीं। 1990 के दशक में भारत ने उदारीकरण की राह पकड़ी और चीन पहले से ही वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में तेजी आई और आजस्थिति यह रहे हैं। रेशम मार्ग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने न केवल वस्तुओं बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान–प्रदान करवाया किंतु आधुनिक काल में जब 1962 का युद्ध हुआ, तो दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई।

देश

दुनिया से

सोशल मीडिया के जाल में फंसते युवा

मनुष्य

की सभ्यता का इतिहास यदि हम गहराई से पढ़ें तो पाते हैं कि हर युग ने अपनी पहचान किसी न किसी माध्यम से रची है। कभी गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरे गए, कभी ताम्रपत्रों और पांडुलिपियों पर शब्द रचे गए। मनुष्य ने जब से शब्द और विचारों को साझा करने की कला सीखी, तभी से उसके जीवन में संचार का महत्व बढ़ता चला गया। कभी चूल्हे के पास बैठकर, कभी गांव की चौपालों में, कभी नदी किनारे गीत गाकर और कभी दरबारों में गाथाएँ सुनाकर लोग अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और अपने विचार एक-दूसरे तक पहुंचाते रहे। कालांतर में जब लिपि और भाषा का विकास हुआ, तो संवाद और ज्ञान का नया संसार खुला। छपाई मशीन के आविष्कार से लेकर रेडियो, टेलीविजन और फिर इंटरनेट तक, हर युग ने इन्सान को अपने-अपने तरीके से जोड़ने की कोशिश की। मनुष्य की सभ्यता की यात्रा हमेशा संचार और संवाद की नई विधाओं से जुड़ी रही है। जब आदिमानव ने पहली बार गुफा की दीवारों पर चित्र बनाये थे, वह अपने अनुभव और कल्पनाओं को स्थायी करने का प्रयास था। जिस तरह प्राचीन युग में गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अपने समय की कहानियां कहती थीं, उसी तरह आज के समय में मोबाइल स्क्रीन पर स्करोल होती रीलें हमारे समाज और संस्कृति की गवाही देती हैं। किंतु फर्क इतना है कि गुफाओं की दीवारें स्थायी थीं, उनमें समय का धैर्य और सृजन का विस्तार था, जबकि आज की डिजिटल रीलें क्षणिक हैं, तेज हैं, और अक्सर सतहीपन के रंगों में रंगी होती हैं। यह अंतर ही हमें बताता है कि क्यों आज सोशल मीडिया, विशेषकर रीलें और पोस्ट्स ने हमारे युवा मन को गहराई से प्रभावित किया है। आज का युग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का युग है। इक्कीसवीं सदी के आरंभ में इंटरनेट के आकाश में जो सबसे बड़ा संस्कृतिक और सामाजिक विस्फोट हुआ, वह था सोशल मीडिया का जन्म जिसने पूरी दुनिया को ‘वैश्विक गांव’ में बदल दिया है। शुरुआत में इनका उद्देश्य सीधा था लोगों को जोड़ना, दूरियों को मिटाना और संवाद को आसान बनाना। इंटरनेट के इस आभासी संसार ने शुरुआती दौर में मित्रता, रिश्तों और विचारों को साझा करने का एक खुला मंच दिया। सोशल मीडिया की यात्रा लगभग दो दशक पुरानी है। बीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब इंटरनेट आम जीवन में

दस्तक देने लगा, तब ही संवाद के नए रूप जन्म लेने लगे। 1997 में ‘सिक्स डिग्रीज’ नामक पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म सामने आया। फिर आईसीक्यू और याहू चैट जैसे माध्यमों ने लोगों को आपसी संवाद का नया स्वाद दिया। धीरे-धीरे इंस्टाग्राम, स्नैपचेट और यूट्यूब ने चित्र, वीडियो

मनुष्य

मनुष्य ने जब से शब्द और विचारों को साझा करने की कला सीखी, तभी से उसके जीवन में संचार का महत्व बढ़ता चला गया। कभी चूल्हे के पास बैठकर, कभी गांव की चौपालों में, कभी नदी किनारे गीत गाकर और कभी दरबारों में गाथाएँ सुनाकर लोग अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और अपने विचार एक-दूसरे तक पहुंचाते रहे। कालांतर में जब लिपि और भाषा का विकास हुआ, तो संवाद और ज्ञान का नया संसार खुला। छपाई मशीन के आविष्कार से लेकर रेडियो, टेलीविजन और फिर इंटरनेट तक, हर युग ने इन्सान को अपने-अपने तरीके से जोड़ने की कोशिश की। मनुष्य की सभ्यता की यात्रा हमेशा संचार और संवाद की नई विधाओं से जुड़ी रही है।

और संगीत को जोड़कर संवाद को और अधिक आकर्षक बना दिया। भारत में यह यात्रा 2000 के दशक के अंत से तेजी पकड़ती है। पहले शहरों में साइबर कैफे के माध्यम से, फिर स्मार्टफोन के प्रसार और सस्ते इंटरनेट ने इसे गांव-गांव तक पहुंचा दिया। 2004 में फेसबुक और ऑकुट जैसी साइटों ने युवाओं को जोड़ा, तो 2006 में ट्विटर ने विचारों को 140 अक्षरों में बांधकर पूरी दुनिया में फैला दिया। इसके बाद यूट्यूब, टिकटोर और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचेट ने इसे और व्यापक बना दिया। शुरु में लोग फोटो और छोटे संदेश साझा करते थे, लेकिन जल्द ही वीडियो का दौर आया। 2020 में इंस्टाग्राम ने रील्स की सुविधा शुरू की, जिसने युवाओं को 15-30 सेकंड की वीडियो के जरिए अपनी प्रतिभा, विचार और भावनाएं व्यक्त करने का नया मंच दिया। आज रील्स मनोरंजन, कला, शिक्षा और यहां तक कि रोजगार का बड़ा जरिया बन चुकी है। यह सब

गुरुवार, 11 सितंबर, 2025

हैदराबाद

गुरुवार, 11 सितंबर, 2025

हैदराबाद



चाहती। उत्पादन लागत भी वहां बढ़ चुकी है। इन सब कारणों से चीन की कंपनियों को नए बाजारों और नए ठिकानों की तलाश है। भारत उनके लिए सबसे स्वाभाविक विकल्प बनकर उभर रहा है, क्योंकि यहाँ विशाल उपभोक्ता बाजार है, श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में है और राजनीतिक स्थिरता भी अपेक्षाकृत बेहतर है। भारत की स्थिति भी निवेश की दृष्टि से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। यहाँ हर साल लाखों युवा शिक्षा पूरी करके विनिर्माण क्षेत्र अभी भी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान नहीं दे पा रहा। “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसे अभियानों का उद्देश्य यही है कि भारत एक मजबूत औद्योगिक शक्ति बने परंतु विदेशी निवेश के बिना यह खोपूरा करना कठिन है। ऐसे में अगर चीन की कंपनियाँ भारत में कारखाने लगाती हैं, उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करती हैं तो यह भारत के लिए एक अवसर साबित हो सकता है। अगर हम संभावित फायदों पर नजर डालें तो सबसे पहला लाभ रोजगार के रूप में दिखाई देता है। लाखों युवाओं और यूरोप ने चीन की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, तकनीकी क्षेत्रों में उसे अलग-थलग करने की कोशिश की है और “चाइना प्लस वन” रणनीति के तहत कंपनियाँ अब केवल चीन पर निर्भर नहीं रहना

बड़ी प्राप्ति की है। अगर यह तकनीक भारत आएगी तो हमारी घरेलू कंपनियाँ भी इसे सीखेंगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाएंगी। तीसरा लाभ निर्यात क्षमता के रूप में सामने आएगा। भारत न केवल अपने उपभोक्ता बाजार को पूरा करेगा बल्कि इन कंपनियों के माध्यम से विदेशों में भी सामान निर्यात कर पाएगा। चौथा लाभ बुनियादी ढाँचे के विकास का होगा, क्योंकि जब निवेश आएगा तो सड़क, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी सुधार होगा। और अंततः यह संभावना बनेगी कि भारत “दुनिया की फैक्ट्री” कहलाने वाले चीन की जगह खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। लेकिन इन सबके बीच चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है। चीन की कंपनियाँ पर कई बार डेटा चोरी और जासूसी के आरोप लगे हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा कि कहीं आर्थिक सहयोग सुखसा के लिए खतरा न बन जाए। दूसरा खतरा घरेलू उद्योगों पर असर का है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली चीनी कंपनियाँ भारतीय लघु और मध्यम उद्योगों को कमजोर कर सकती हैं जिससे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्रभावित होगा। तीसरा खतरा आर्थिक निर्भरता का है। अगर भारत बहुत अधिक चीन पर निर्भर हो गया और भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई राजनीतिक विवाद हुआ तो भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। चौथा खतरा नीति और भ्रष्टाचार से

जुड़ा है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत को नीतियाँ स्पष्ट करनी होंगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा अन्यथा निवेशक असुरक्षित महसूस करेंगे। दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों से भारत की तुलना की जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ताइवान सभी इस दौड़ में हैं। वियतनाम की नीतियाँ और व्यापारिक सुगमता भारत से बेहतर मानी जाती हैं, बांग्लादेश वस्त्र उद्योग में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, ताइवान तकनीक में आगे है और चीन से दूरी बनाए रखना चाहता है परंतु भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है, जो इन देशों के पास नहीं है। यही कारण है कि चीन की कंपनियाँ भारत को प्राथमिकता दे रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है कि भारत निवेश का स्वागत तो करे, लेकिन शर्तों के साथ। रक्षा, संचार और डेटा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीन की कंपनियों को सीमित किया जाए। हर निवेश अनुबंध में तकनीकी हस्तांतरण की शर्त रखी जाए ताकि भारतीय उद्योग भी सीख सकें। छोटे उद्योगों को सुरक्षा कवच दिया जाए ताकि वे प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। विदेशी निवेश की निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगर भारत इन शर्तों के साथ निवेश स्वीकार करता है तो आने वाले दस-पंद्रह वर्षों में उसका चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। पॉच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना साकार हो सकता है, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और रोजगार का महासांत खुल सकता है। परंतु अगर हमने बिना सोचे-समझे औंध खोपूरा निवेश स्वीकार कर लिया तो भविष्य में हम वहीं गलती दोहरा सकते हैं जो कई छोटे देशों ने की जहाँ विदेशी कंपनियाँ ने स्थानीय उद्योगों को समाप्त कर दिया और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जमा लिया। इसलिए भारत को इस निवेश अवसर को बखूबी तरीक ही लेना होगा, मजबूरी की तरह नहीं। निवेश तभी सार्थक है जब वह आत्मनिर्भरता, तकनीकी विकास और सामाजिक स्थिरता को मजबूत करे। यही निवेश का नया दौर है और यही भारत के लिए असली परीक्षा।

आप का नजरिया

फिलहाल 1500 करोड़

राहत

बटोरने के परिश्रम में लगी हिमाचल सरकार के सामने कुछ बदल अवश्य छंटे हैं। आपदा से ग्रस्त हिमाचल ने अपनी फरियಾದ को किसितयां चलाई, उन पे बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंततः हिमाचल में राहत के टापू तक पहुंचे। कई दिनों की कसरतें, सत्ता-विपक्ष के प्रयत्न, सांसदों की चिट्ठियां और जनता की चीखो-पुकार के बीच प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ की राहत का पैगाम दिया है। गगल हवाई अड्डे पर एक उच्च स्तरीय बैठक, वकालत और दुख के दृश्य में तैरते मानवीय सवालों का उत्तर देते प्रधानमंत्री ने फिलहाल 1500 करोड़ का इंतजाम तो कर ही दिया। यह दीगर है कि अकेले सराज विधानसभा के नुकसान की ही पूर्ण भरपाई करनी हो, तो यह किस्त भी छोटी पड़ जाएगी, फिर भी राहत की एक गुंजाइश बनती है। तो प्रदेश फौरी तौर पर पुर्ननिर्माण के आरंभिक कदम ले पाएगा। प्रदेश में नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र को अभी अपनी उदारता, सदायशता और ईमानदारी फिलहाली होगी, क्योंकि अभी हिमाचल की आहें पूरी तरह सुनी नहीं गई हैं। शहर और गांव आज भी प्यासे हैं, क्योंकि जलापूर्ति की नब्बे फीसदी परियोजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। इसी तरह सड़कें भी सत्तर फीसदी बर्बाद हो चुकी हैं और कहीं-कहीं तो नामोनिशान भी मिट चुका है। कृषि क्षेत्र में सब्जियां और फसलें अब अगले सीजन तक अपनी हानि के मातम में हैं, तो ग्रामीण आर्थिकी पर यह कहर पूरी तरह टूट कर बरसा है। नुकसान का वास्तविक आकलन अभी नहीं हुआ है। यहां मानवीय आधार पर देखें तो कितने ही घर, कितने ही कुनबे, कितने ही गांव और बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। राहत की व्याख्या को व्यापक आधार चाहिए। एक ओर अल्पावधि भरपाई है, तो दूसरी ओर दीर्घकालीन सहायता योजना की दरकार हिमाचल के भविष्य को रहेगी। प्रदेश का पूरा पर्यटन उद्योग मिट्टी में मिल गया है। ऐसे में राहत के सीमित दायरे को पुनर्वस को व्यापकता में दीर्घकालीन योजनाओं से जोडना होगा। थुनांग जैसे कस्बे को फिर से बसाने के लिए वहां एक टाउनशिप परियोजना की जरूरत है। पूरे प्रदेश की जल निकासी को एक खास प्रबंधन के तहत देखते हुए प्रमुख खड्डों, नालों व कूहलों के चैनलाइजेशन की जरूरत है। प्रदेश में निर्माण के मानदंड सुनिश्चित करते हुए केंद्र प्रदत्त योजनाओं की लागत का अनुमान बढ़ाना पड़ेगा। पूरे हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय परिस्थिति, आर्थिकी तथा पर्यावरणीय सहयोग को देखते हुए भू-राजस्व तथा वन मिलकीयत के बीच एक नए रिस्ते का कारगर चाहिए। राज्य की 68 प्रतिशत वन भूमि के दबाव में ही निर्माण असुरक्षित स्थानों पर होने लगा है। वन भूमि किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से

अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि जंगलों के तहत मापी गई भौगोलिक दृष्टि से अति सुरक्षित तथा वंजर जमीनों को पुनर्वास, पुर्ननिर्माण तथा आर्थिकी निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जा सके। वन नीति के कवामन फामूरे के कई धावक विन्द पैदा हुए हैं, अतः राज्य सरकार को आगे बढने तथा नागरिकों के बचाव की अनिवार्यता में वन संरक्षण अधिनियम के कुछ बाढ़ हटाने पड़ेगे। अंत में हिमाचल जैसे राज्य की तकदीर का फैसला अब वार्षिक फंडिंग के तहत अन्याय ही कर रहा है। एक लाख करोड़ के कर्ज तले दबे पर्वतीय राज्य को अटल सरकार की तरह आपदा,

आपदा

आपदा से ग्रस्त हिमाचल ने अपनी फरियಾದ की जो किसितयां चलाई, उनपे बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंततः हिमाचल में राहत के टापू तक पहुंचे। कई दिनों की कसरतें, सत्ता-विपक्ष के प्रयत्न, सांसदों की चिट्ठियां और जनता की चीखो-पुकार के बीच प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ की राहत का पैगाम दिया है। गगल हवाई अड्डे पर एक उच्च स्तरीय बैठक, वकालत और दुख के दृश्य में तैरते मानवीय सवालों का उत्तर देते प्रधानमंत्री ने फिलहाल 1500 करोड़ का इंतजाम तो कर ही दिया। यह दीगर है कि अकेले सराज विधानसभा के नुकसान की ही पूर्ण भरपाई करनी हो, तो यह किस्त भी छोटी पड़ जाएगी, फिर भी राहत की एक गुंजाइश तो पूरी हुई। बारिश के बाद केंद्र से राहत की तैयारी तो शुरू हुई। राहत के अनेक पड़ाव हो सकते हैं और अगर पंद्रह सौ करोड़ की राशि एकमुश्त पैकशक बनती है, तो प्रदेश फौरी तौर पर पुर्ननिर्माण के आरंभिक कदम ले पाएगा। प्रदेश में नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र को अभी अपनी उदारता, सदायशता और ईमानदारी दिखानी होगी, क्योंकि अभी हिमाचल की आहें पूरी तरह सुनी नहीं गई हैं। शहर और गांव आज भी प्यासे हैं, क्योंकि जलापूर्ति की नब्बे फीसदी परियोजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। इसी तरह सड़कें भी सत्तर फीसदी बर्बाद हो चुकी हैं और कहीं-कहीं तो नामोनिशान भी मिट चुका है। कृषि क्षेत्र में सब्जियां और फसलें अब अगले सीजन तक अपनी हानि के मातम में हैं, तो ग्रामीण आर्थिकी पर यह कहर पूरी तरह टूट कर बरसा है।

कनेक्टिविटी, आर्थिकी व पर्यटन जैसे पैकेज तुरंत मिलने चाहिए। सरकार और विपक्ष ने मिलकर प्रयानमंत्री से जो हासिल किया है, वह अभी थोड़ा है, बहुत अभी बाकी है।



पेपर व्यापार में जीएसटी की विसंगति पर व्यापारी चिंतित द लखनऊ पेपर मर्चेण्ट्स एसोसिएशन ने जताई चिंता

लखनऊ, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

लखनऊ पेपर मर्चेण्ट्स एसोसिएशन ने हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा एचए-सएन 4802 (पेपर) पर दोहरे कर दर लागू करने के निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस सिलसिले में एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से मिला और आग्रह किया कि इस निर्णय को शीघ्र समीक्षा की जाए तथा सीबीआईसी एवं जीएसटी परिषद से कागज तथा एक्सरसाइज बुक पर एक समान दर से कर लागू करने का अनुरोध किया जाए, ताकि व्यापार, उद्योग और सुशासन के हितों की रक्षा हो सके। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय काबरा, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता विष्णु अग्रवाल और उमेश गोयल शामिल थे।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि निल-रेटेंड पेपर हेतु कोई भी व्यावहारिक व्यवस्था असंभव है। सरकार ने प्रस्ताव किया है कि अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु आपूर्ति किए गए पेपर पर शुन्य जीएसटी लगेगा, जबकि अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु आपूर्ति किए गए उसी पेपर पर 18 प्रतिशत जीएसटी



लगाया जाएगा। एसोसिएशन ने इंगित किया है कि ऐसी आपूर्ति को सही ढंग से अलग-अलग करना संभव नहीं है क्योंकि मिल और वितरक अंतिम उपयोग की पुष्टि नहीं कर सकेंगे। इससे अनिवार्य रूप से दुरुपयोग, मुकदमेबाजी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि यह एक अनोखी एवं अव्यवहारिक पहल की शुरुआत है। यद्यपि जीएसटी कानून में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां एचएसएन कोड के अंतर्गत अलग-अलग उत्पादों पर अलग-अलग दरें लागू हैं—जैसे चीनी बनाम खांडसारी, लकड़ी के फर्नीचर बनाम प्लास्टिक/लौह फर्नीचर, जीवन

रक्षक दवाइयां बनाम अन्य दवाइयां—परंतु ये सभी उत्पाद भिन्नता पर आधारित हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसी उत्पाद पर, उसी एचएसएन के अंतर्गत केवल अंतिम उपयोग के आधार पर भिन्न रूप से दरें लागू की गई हैं, जो अभूतपूर्व और अव्यवहारिक है।

बिल ऑफ सप्लाई से बड़ा जोखिम निल-रेटेंड आपूर्ति के लिए विक्रेताओं को टैक्स इनवॉइस के स्थान पर बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होगा। चूंकि बिल ऑफ सप्लाई पर ई-इन्वॉयसिंग प्रणाली लागू नहीं होती, यह भ्रष्टाचार और राजस्व हानि की संभावना बढ़ाता है। साथ ही मिलों, वितरकों और छोटे

निर्माताओं पर अतिरिक्त अनुपालन का बोझ भी डालता है।

एसोसिएशन का दृढ़ मत है कि आगे बढ़ने का एक मात्र व्यवहारिक मार्ग यही है कि कागज और अभ्यास पुस्तिकाओं दोनों पर समान रूप से 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए। एक समान 5 प्रतिशत जीएसटी दर से अनुपालन सरल होगा, दुरुपयोग रहेगा और सभी हितधर—परकों—पेपर मिलों, वितरकों तथा कंटेज उद्योग में कार्यरत लाखों छोटे अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं—को लाभ होगा। साथ ही राज्य के राजस्व को भी कोई हानि नहीं होगी।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय काबरा ने कहा कि एसोसिएशन की यह मांग व्यापारियों और उद्योग के हित में पूरी तरह व्यावहारिक है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि मामले को केंद्र सरकार तथा जीएसटी परिषद के समक्ष उचित रूप से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं और व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डुंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत मंजूर

प्रयागराज, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई थी, जिसे न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इस तरह समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लगाई थी।

12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की।

जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की याचिका पर फैसला सुनाते बुधवार को उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में आजम खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली दस साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है।

दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील के

लंबित रहने तक जमानत देने की कोर्ट से मांग की थी। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली की जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। दोनों की क्रिमिनल अपील पर एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 30 मई 2024 को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां को दस साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को सात साल की सजा सुनाई गई थी। आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद पक्ष रखा।

डुंगरपुर प्रकरण में अबरार नाम के व्यक्ति ने सपा नेता आजम खां, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली उर्फ फकीर मोहम्मद समेत तीन लोगों के खिलाफ अगस्त 2019 में रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता अबरार के मुताबिक दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खां और बरकत अली ठेकेदार ने उसके साथ मारपीट की थी।

घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके साथ ही उसके मकान को तोड़ भी दिया था। तीन साल बाद 2019 में अबरार ने थाना गंज में मामला दर्ज कराया था।

इस मामले में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को सात साल की सजा सुनाई थी। डुंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में रामपुर के गंज थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे।

टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ यूपी के शिक्षक

अक्टूबर में यूपी के शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे

लखनऊ, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार को प्रदेशभर से शिक्षकों द्वारा पहले दिन ही 97890 पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षक खिंतित और डरे हुए हैं। अगर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस मामले में हस्तछेप नहीं करते हैं तो उनके सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के आह्वान

पर बुधवार को प्रदेश भर से शिक्षकों द्वारा पहले दिन ही 97890 पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेशभर के शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा की 55 साल का शिक्षक कैसे परीक्षा पास कर पाएगा।

अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाए या अब खुद पढ़े। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार के कानून और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से प्रदेश के काफी शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहराया है। केंद्र सरकार व एनसीटीई चाहे तो शिक्षकों को राहत मिल सकती है।

अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो अक्टूबर में देश भर के शिक्षक

दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे। दूसरी ओर एक शिक्षक संगठन की ओर से प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर बुधवार को प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन दिया गया।

संगठन के सुशील कुमार पांडेय ने मांग की कि आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों को इससे मुक्त रखा जाए। आरटीई एक्ट में संशोधन किया जाए। वहीं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन 11 से 25 सितंबर के बीच पीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने हम पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए अभियान चलाएंगे। प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि संगठन शिक्षकों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा।

मणिपुर की महिला और उसके नाइजीरियन दोस्त का कारनामा

शिक्षिका से ठग लिए 94.78 लाख रुपए

मुरादाबाद, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

मुरादाबाद निवासी शिक्षिका से मणिपुर निवासी महिला और उसके नाइजीरियन साथी ने 94.78 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। पुलिस ने दिल्ली से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में रहने वाली शिक्षिका से मणिपुर की महिला ने नाइजीरियन साथी के साथ मिलकर 94.78 लाख रुपए की साइबर ठगी की थी। मंगलवार को साइबर थाने की पुलिस ने दिल्ली में रह रही मणिपुर निवासी कोलसम सुनीता को गिरफ्तार कर साइबर ठगी का खुलासा किया।

टीम महिला के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से लैपटॉप, डेबिट कार्ड, मोबाइल, चेकबुक, सिमकार्ड और 20 हजार रुपए बरामद किए हैं।



एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि कटघर क्षेत्र में रहने वाली शिक्षिका ने साइबर थाने में 94.78 लाख रुपए ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल करते हुए साइबर पुलिस ने दिल्ली के उत्तमनगर ओम विहार में रह रही मणिपुर प्रदेश के चंदेल जिले के चापिकारोंग निवासी कोनसम सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह नाइजीरियन युवक और अन्य ठगों के साथ मिलकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम देती है।

वह मेट्रीमोनियल साइट पर नई-नई प्रोफाइल पर नजर रखती है। 25 जुलाई को शिक्षिका ने अपनी प्रोफाइल बनाई थी तो नाइजीरियन युवक ने शिक्षिका के पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उसने अपना नाम डॉ. अरव सिंह बताते हुए कहा कि अमेरिका में जनरल सर्जन है। वह भारतीय लड़की से शादी कर भारत में ही बसना चाहता है। साइबर ठग ने शिक्षिका से कहा कि वह पार्सल भेज रहा है। शिक्षिका ने आरोपी महिला के बताए खाते में तीस

हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। महिला ने दोबारा कॉल कर शिक्षिका को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की धमकी देकर 31 जुलाई से 18 अगस्त के बीच कुल 94.78 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए।

पुलिस ने आरोपी महिला के पास से लैपटॉप, डेबिट कार्ड, मोबाइल, चेकबुक, सिम और रकम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। इस गिरोह के अन्य ठगों की तलाश की जा रही है।

मणिपुर के चंदेल जिले के चापिकारोंग निवासी कोनसम सुनीता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 15 साल पहले वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी। काफी प्रयास के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास उसकी एक युवक से मुलाकात हुई। उसने नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद महिला युवक

के साथ चली गई। युवक और उसके साथी लोगों से साइबर ठगी करते थे। महिला ने कुछ दिन उनके साथ काम किया। बाद में उसकी मुलाकात नाइजीरियन युवक से हुई। इसके बाद महिला उसके साथ मिलकर ठगों को ठगना शुरू कर दिया।

साइबर ठगों के गिरोह में शामिल कोनसम सुनीता ने ही पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के ठगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और लोन दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेज ले लिए थे। इसके बाद इन दस्तावेजों के जर्जर बैंकों में खाते खुलवाए। इनके डेबिट कार्ड और चेकबुक अपने पास रख ली थी। फिर साइबर ठगी करने के बाद रकम इन खातों में मंगवाई जाती थी। फिर ऑनलाइन ही रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते थे।

संभल में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यूनिट शुरू

आतंकी गतिविधियों की कई नई-पुरानी फाइलें खुलेंगी

संभल, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

संभल में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) यूनिट का अस्थायी कार्यालय शुरू हो गया है। वर्ष 1990 के बाद से लापता हुए संभल के कई युवक आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए, तभी से खुफिया एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुई थीं। अब एटीएस की इकाई उन सभी नई-पुरानी फाइलों को खंगालेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

एटीएस के अधिकारी ने बताया कि संभल के दो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की सजा भी काट चुके हैं। कई की तलाश देश की सभी बड़ी खुफिया एजेंसी कर रही हैं। एक आतंकी अमेरिका के हमले में मारा जा चुका और एक एक युवक आतंकवादी होने के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद है।



इन गतिविधियों के कारण संभल जिला खुफिया एजेंसियों की रडार पर रहा है। दीपा सराय निवासी मोहम्मद उस्मान देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोपी है और 2023 से देश में भगोड़ा घोषित है। फिलहाल वह पाकिस्तान की जेल में बंद है। उस्मान के सम्पर्क संभल में किन

लोगों से हैं इसकी छानबीन भी हो रही है। वर्ष 2005 में उसका नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आया था। दिल्ली की स्पेशल सेल उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन पता चला कि वह पाकिस्तान की जेल में बंद है।

दीपा सराय निवासी शरजिल

और सईद अख्तर 1998 में लापता हुए थे। इन दोनों को ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तलाश कर रही है। स्पेशल सेल के अनुसार यह दोनों आतंकवादी हैं और इनके पोस्टर भी दिल्ली के थानों में लगे हैं। इनके बारे में कई सुराग नहीं मिला और यह जिंदा हैं या मर गए। इसकी भी पुष्टि 27 वर्ष के अंदर नहीं हुई। पहली बार जानकारी 2005 में सामने आई थी। जब खुफिया एजेंसियां इन लोगों के परिजनों से पूछताछ करने के लिए पहुंची। दीपा सराय निवासी मौलाना आसिम उमर उर्फ शत्रू अलकायदा का दक्षिण एशिया प्रमुख था। वह 1998 में संभल से लापता हुआ था। वर्ष 2016 में अमेरिका ने आतंकियों की सूची जारी की थी। इसमें उसका नाम शामिल था। वर्ष 2019 में अमेरिका के हमले में मारा गया।

सूत्रों का कहना है कि मौलाना आसिम उमर जिस समय लापता हुआ था। उसके अगले पांच वर्ष के अंदर कई युवक लापता हुए थे। उनमें किसी की गुमशुदगी तक दर्ज नहीं हुई।

24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी की छानबीन में सामने आया कि देश का बड़ा वाहन चोर शारिक साटा गिरोह के सदस्यों ने गोली चलाई थी। इन आरोपियों ने पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल किया था। तीन आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। शारिक साटा का नाम हवाला कारोबार, हथियार तस्करी से भी जुड़ा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी सम्पर्क होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट के मामले में यह रिपोर्ट दर्ज की थी।

संभल के सपा सांसद ने खुद तोड़वाया गैरकानूनी घर

संभल, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

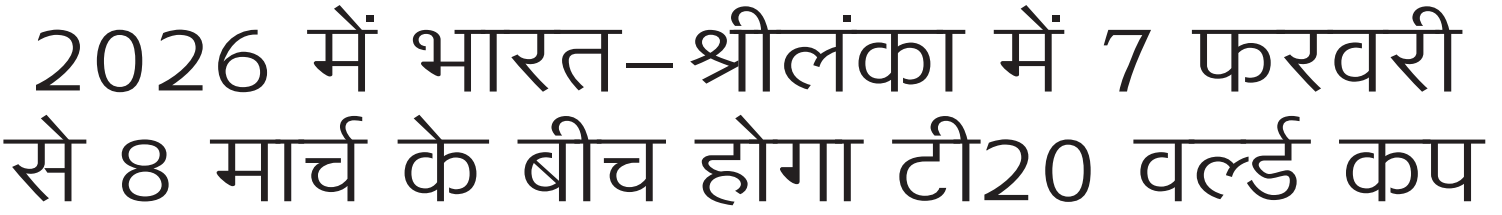
संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण को हटवाना शुरू कर दिया है। एसडीएम विकास चंद्र के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। बिना अनुमति निर्माण करने पर सांसद पर 1.35 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था।

संभल से सपा के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान में जो निर्माण कार्य कराया, उसे अब हटवाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को निर्माण हटाने का काम हुआ। एसडीएम विकास चंद्र के आदेश के बाद इसे हटवाया जा रहा है। संभल दंगे के दौरान यह मामला सुर्खियों में आया था। इस मामले में नियत प्राधिकारी/एसडीएम



विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है और इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसके चलते सांसद पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसे सांसद ने तत्काल ही

भरवा दिया था। एसडीएम/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, संभल विकासचंद्र ने बताया कि सांसद ने अपने आवास में कुछ निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कराया था। जिसकी सुनवाई पूरी करके इसे हटाने के आदेश दिए थे। साथ ही, जुर्माना भी लगाया था। सांसद ने इसे हटवाना शुरू कर दिया है।



फिलहाल अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए केवल 15 टीमों ही क्वालीफाई कर पाई हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और पहली बार खेल रहा इटली भी शामिल हैं।

LOST OF DOCUMENT
I, SHOBHA BAI W/O LATE N RAMLAJ,
R/O. HNO: 14-8-180, CHUDI BAZAR,
BEGUM BAZAR, HYD-500012, T.G
Lost of my CANCELLATION OF
AGREEMENT OF SALE-
CUM GENERALPOWER OF
ATTORNEY (WITH POSSESSION)
Bearing Registration No. 1061/2010,
at SRO Doodhbowli, on25-08-2025 at
around 12-30 P.M. at Begum Bazar,
Hyderabad, IF ANY ONE FOUND
PLEASE CONT:9393476007



एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ 11 से खुलेगा

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी का इश्यू जल्द खुलने वाला है। अगर आईपीओ में निवेश की योजना बना रहे हैं तो कंपनी का रूपए 91.10 करोड़ का यह एसएमई आईपीओ 11 सितंबर 2025 से निवेशकों के लिए खुलेगा और 15 सितंबर तक इसमें पैसा लगाया जा सकेगा। इस इश्यू का प्राइस बैंड रूपए 133 से रूपए 140 प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 18 सितंबर को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होने की संभावना है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, एयरफ्लोआ

रेल टेक्नोलॉजी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम रूपए 150 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग के समय निवेशकों को अपने निवेश पर 107 प्रतिशत से अधिक का संभावित रिटर्न मिल सकता है। कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है और यह भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रोलिंग स्टॉक के कलपुर्जों के निर्माण का काम करती है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री और अन्य रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए पुर्जें उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कंपनी रेलवे के टर्नकी इंटीरियर फर्निशिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है।

यूरोपीयसंघने102नएभारतीयमत्स्यप्रतिष्ठानों कोनिर्यातकेलिएमान्यतादी

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत के 102 नए मत्स्य प्रतिष्ठानों को अपने सदस्य देशों को समुद्री खाद्य निर्यात के लिए मान्यता प्रदान की है। यह कदम भारत के समुद्री खाद्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस निर्णय से भारत की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों पर यूरोपीय संघ का विश्वास बढ़ा है। विशेष रूप से जलीय कृषि के डींगी और सेफेलोपोड्स जैसे रिक्रड, कटल फिश और ऑक्टोपस के निर्यात में वृद्धि होगी। इससे भारत को यूरोपीय और अन्य विदेशी बाजारों में प्रवेश के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही इस उद्योग में रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है, जो आर्थिक विकास के लिए सहायक होगा। यह कदम भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।



न्यूज़ ब्रीफ

जीएसटी कटौती से ऑटो सेक्टर में आई तेजी, बाजार पूंजीकरण में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी



नई दिल्ली। सरकार द्वारा वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़ी कटौती की घोषणा के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नया बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को एक दशक में सबसे बड़ी टैक्स राहत का ऐलान किया था, जिसके तहत अधिकतर यात्री वाहनों पर जीएसटी दर 31 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई। इसका सीधा असर ऑटो सेक्टर पर देखने को मिला है। निपटी ऑटो इंडेक्स, जो 15 प्रमुख वाहन कंपनियों को ट्रैक करता है, तब से अब तक करीब 3 लाख करोड़ रुपये (लगभग 34 अरब डॉलर) का बाजार पूंजीकरण जोड़ चुका है। इंडेक्स में 12.7 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है, जो इसी अवधि में निपटी 50 की महज एक फीसदी की बढ़त की तुलना में कहीं ज्यादा है। मारुति सुजुकी इंडिया, जो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी वाहन निर्माता है, के शेयर में 19 फीसदी की वृद्धि हुई है। आयशर मोटर्स और टीवीएस मोटर जैसी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां भी इस तेजी में अग्रणी रही हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एक विश्लेषक शशांक का कहना है कि यह ऑटो सेक्टर के लिए रोमांचक समय है। उनका मानना ​​है कि कर कटौती से कंपनियों कीमतें घटाएंगी, जिससे खासकर एंटी-लेवल कारों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ ने वैश्विक बाजार की धारणा को प्रभावित किया है, लेकिन घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन से पहले मांग में मजबूती बनी हुई है।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चा तेल 49 रुपये चढ़ा



नई दिल्ली। कतर में हमस नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इंजरायली हमले के बाद पश्चिम क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने की चिंताओं के बीच बुधवार को वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 49 रुपये बढ़कर 5,593 रुपये प्रति बैरल हो गईं। मल्टी कम्प्रीडि एक्सचेंज (एमसीएक्स) में सितंबर डिलिवरी के लिए सबसे अधिक कारोबार वाले कच्चे तेल के वायदा भाव 49 रुपये या 0.88 प्रतिशत बढ़कर 5,593 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसमें 10,812 लॉट के लिए कारोबार हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कच्चा तेल 1.18 प्रतिशत बढ़कर 63.37 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि ब्रेंट क्रूड 1.17 प्रतिशत बढ़कर 67.17 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर शुरू ट्रंप ने मोदी को बताया अच्छा दोस्त



वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों में सुधार का संकेत देते हुए घोषणा की है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्यू सोशल पर लिखा कि दोनों देश व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'बहुत अच्छा दोस्त' बताया और कहा कि वह जल्द ही उनसे बातचीत के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 'महान प्रधानमंत्री' करार देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पुरा भरोसा है कि हमारे दोनों देशों के लिए व्यापार वार्ता सफल रहेगी। ट्रंप के इस नरम रुख के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी बातों की सराहना की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बताया। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ और उनका पूरा समर्थन करता हूँ। यह कदम अमेरिका की ओर से हाल ही में टैरिफ बढ़ाने के बाद आया है। 27 अगस्त को अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। यह निर्णय भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखने के कारण लिया गया था। इसके कारण दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया था। अब व्यापार वार्ता के फिर से शुरू होने से उम्मीद जताई जा रही है कि इस तनाव को कम किया जा सकेगा और द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी।

लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार निवेशकों को 1 दिन में 2.65 लाख करोड़ का हुआ मुनाफा

नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

मजबूत ग्लोबल संकेतों और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बढ़ी उम्मीद की वजह से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल बना रहा। के कारोबार के दौरान दिन के पहले सत्र में लगातार खरीदारी होती रही। हालांकि दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण सेंसेक्स और निफटी दोनों सूचकांकों की चाल में गिरावट भी आई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.40 प्रतिशत और निफटी 0.42 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए।

दिनभर के कारोबार के दौरान आईटी सेक्टर में लगातार दूसरे दिन जमकर खरीदारी होती रही। इसके साथ ही बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में भी लगातार खरीदारी होती रही। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, कैपिटल गूड्स, मेटल, ऑयल एंड गैस और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयरों में लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। बॉंड मार्केट में भी लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.84 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ के कारोबार का अंत किया।

शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारोबार के बाद बढ़ कर 456.49 लाख करोड़ रुपये (अर्नात्म) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 453.84 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को के कारोबार से करीब 2.65 लाख करोड़ रुपये का फायदा हो गया।

दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,282 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,409 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,717 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं



156 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई के सपोर्ट से सुबह 10:30 बजे तक ये सूचकांक 167.10 अंक की छलांग लगा कर 25,035.70 अंक तक पहुंच गया। हालांकि दोपहर 11 बजे के बाद बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में गिरावट आ गई। बिकवाली के दबाव की वजह से शाम 3 बजे के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक फिसल कर 24,915.05 अंक आ गया। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में हुई खरीदारी के सपोर्ट से निफ्टी निचले स्तर से करीब 60 अंक की रिकवरी करके 104.50 अंक की बढ़त के साथ 24,973.10 अंक के स्तर पर बंद हुआ। पूरे दिन के कारोबार के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.33 प्रतिशत, विप्रो 2.65 प्रतिशत, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.58 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 2.06 प्रतिशत और टीसीएस 1.99 प्रतिशत की मजबूती के साथ के टॉप 5 गेनर्स की सूची में शामिल हुए। दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.49 प्रतिशत, मारुति सुजुकी 1.67 प्रतिशत, बजाज ऑटो 1.48 प्रतिशत, हीरो मोटोकॉर्प 1.35 प्रतिशत और अल्ट्राटेक सीमेंट 0.75 प्रतिशत की कमजोरी के साथ के टॉप 5 लूजर्स की सूची में शामिल हुए।

सूचकांक की चाल में भी तेजी आ गई। खरीदारी के सपोर्ट से सुबह 10:30 बजे तक ये सूचकांक 167.10 अंक की छलांग लगा कर 25,035.70 अंक तक पहुंच गया। हालांकि दोपहर 11 बजे के बाद बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में गिरावट आ गई। बिकवाली के दबाव की वजह से शाम 3 बजे के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक फिसल कर 24,915.05 अंक आ गया। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में हुई खरीदारी के सपोर्ट से निफ्टी निचले स्तर से करीब 60 अंक की रिकवरी करके 104.50 अंक की बढ़त के साथ 24,973.10 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

पूरे दिन के कारोबार के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.33 प्रतिशत, विप्रो 2.65 प्रतिशत, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.58 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 2.06 प्रतिशत और टीसीएस 1.99 प्रतिशत की मजबूती के साथ के टॉप 5 गेनर्स की सूची में शामिल हुए। दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.49 प्रतिशत, मारुति सुजुकी 1.67 प्रतिशत, बजाज ऑटो 1.48 प्रतिशत, हीरो मोटोकॉर्प 1.35 प्रतिशत और अल्ट्राटेक सीमेंट 0.75 प्रतिशत की कमजोरी के साथ के टॉप 5 लूजर्स की सूची में शामिल हुए।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

घर भारत में...

आजादी के बाद 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि ने सुगौली को आधार बनाया, लेकिन सीमा मुद्दे अनसुलझे हैं। आज भी दोनों देश इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बनी हुई हैं। दरअसल, राजनीतिक दबाव से बात अटक जाती है।

भारत-नेपाल सीमा का सबसे बड़ा करीब 729 किमी हिस्सा बिहार से लगता है। यहां के लोग नेपाल के तराई इलाकों से इतने जुड़े हैं कि इसे रोटी-बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे के यहां रोटी खाते हैं और बेटीयां ब्याहते हैं। भाषा भी मिलती-जुलती है, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी और नेपाली का मिश्रण। नेपाल के तराई में रहने वाले मैदानी लोग बिहार के लोगों से सांस्कृतिक रूप से बहुत करीब हैं। रोजमर्रा की ज़िंदगी में ये जुड़ाव साफ दिखता है। नेपाली लोग भारत में इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि नेपाल में स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं। बिहार के अस्पतालों में नेपाली मरीज आम हैं। व्यापार भी खूब होता है सब्जियां, अनाज और दैनिक सामान सीमा पार आते-जाते हैं। शादियां दोनों तरफ होती हैं, जो परिवारों को जोड़ती हैं। लेकिन हाल के सालों में ये रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं।

नेपाल में कोई भी तनाव होता है, तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। किसान अपने खेतों तक जाने के लिए सीमा पार करते हैं, लेकिन उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं। समस्या यह है कि कई किसानों का घर तो भारत में है, लेकिन उनके खेत और खलिहान नेपाल की जमीन पर हैं। ये किसान सालों से अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी करते आए हैं, लेकिन अब सख्ती ने सबकुछ उलट-पुलट कर दिया है। किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए घंटों पूछताछ से गुजरना पड़ता है। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी तक ले जाना मना है, जिससे फसल कटाई, लाने और नई बुआई में भारी दिक्कत हो रही है। ऊपर से नेपाल सरकार ने जमीन बिक्री के नियम कड़े कर दिए हैं। अब भारतीय किसान अपनी जमीन केवल नेपाली नागरिकों को ही बेच सकते हैं और वो भी कम दाम पर।

नेपाल के नागरिकों द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र, खासकर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जैसे जिलों में अतिक्रमण की खबरें सामने आई हैं। नेपाल के लोग भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और फर्जी दस्तावेज बनाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोट आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल कर रहे हैं। ये लोग भारतीय नागरिकों की तरह सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। नेपाल से सटे सीमावर्ती गांवों में ये गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। कुछ लोग शादी के बहाने या अन्य तरीकों से भारत में बस रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं। इससे भारत की सुरक्षा और सीमा की अखंडता पर खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कुछ मामलों में कार्रवाई शुरू की है, लेकिन समस्या अब भी गंभीर है। इस स्थिति ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को और जटिल कर दिया है, खासकर सुगौली संधि से जुड़े क्षेत्रों को लेकर।

भारत-नेपाल सीमा पर फैसिंग क्यों नहीं है? वजह साफ है दोनों देशों के लोगों का आपसी मेल-जोल। अगर दीवार बना दी तो रोटी-बेटी का रिश्ता

टूट जाएगा। सरकारें कहती हैं कि खुली सीमा दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। 1970-80 के दशक में चीनी कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सामान्य तस्करी होती थी। धीरे धीरे यह संगठित अपराध बनता चला गया। सोना, नशीले पदार्थ, हथियार और मानव तस्करी ने पूरे भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया। इस प्रदूषण को बढ़ावा दिया इस्लामिक कट्टरपंथियों और पाकिस्तान परस्त तत्वों ने। अब तो इसमें बांग्लादेशी और रोहिंया घुसपैठिये भी शामिल हो गए हैं।

सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की आईएसआई से है। आईएसआई नेपाल को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। नेपाल की खुली सीमा से घुसपैठ आसान है। आईएसआई ने नेपाल में अड्डे बना रखे हैं, जहां से भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिशें रची जाती हैं। उदाहरण के लिए लश्कर ए तैयबा, खालिस्तान और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के लोग नेपाल रूट से भारत आते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया, जो आईएसआई को भारतीय सिम कार्ड सप्लाई कर रहा था। पाकिस्तानी एजेंट नेपाल की राजनीति में घुस गए और महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए। मिर्जा दिलशाद बेग, अफताब आलम जैसे दर्जनों पाप हैं जिन्होंने नेपाल का पूरा माहौल सड़ा कर रखा दिया।

नेपाल की सीमा धर्मांतरण के धंधे से भी भर गई। नेपाल में इस्लामी आबादी तेजी से बढ़ी। खासकर तराई इलाकों में। पाकिस्तानी फंडिंग से नेपाल में मस्जिदें बना रही हैं और गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ मुस्लिम आबादी बढ़ने से कट्टरवाद फैलता जा रहा है। नेपाल में हिंदू बहुल समाज था, लेकिन अब इस्लामी संगठन सक्रिय हैं, जो गोहत्या और बौध् खाने की मांग कर रहे हैं। भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी ये असर दिखता है, जहां जनसांख्यिकीय असंतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। अगर इस पर समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो जल्दी ही नेपाल भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह का एक और व्याकुल देश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और भारतवासियों की ज़िंदगी दुःख करता रहेगा।

अब अंतरिम...

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का समर्थन किया। पहले काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह का नाम चल रहा था, लेकिन अब वह नाम पीछे रह गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमैन धिसिंग, सागर ढकाल और हर्क साम्पांग जैसे नामों का भी जिक्र हुआ था। लेकिन अब तक किसी चयनित नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

10 दिन में...

यह एसओपी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा अक्टूबर 2024 में दिए गए उस निर्णय के बाद लागू किया गया है जिसमें कहा गया था कि असम सरकार को 1950 के कानून का उपयोग करने की पूरी आजादी है। इस फैसले को असम में दशकों से चली आ रही घुसपैठ की समस्या से निपटने में एक निर्णायक बदलाव माना जा सकता है। सीएम हिमंत ने यह भी साफ किया कि विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित

सेडान डिजायर पर 25,000 रुपये के खास ऑफर की घोषणा



नई दिल्ली, 10 सितंबर (एजेंसियां)।

अपनी पॉपुलर सेडान डिजायर पर मारुति सुजुकी ने खास ऑफर की घोषणा की है। वाहक इस ऑफर का लाभ नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। सेडान डिजायर कार पर अधिकतम 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 10,000 रुपये का कंज्यूमर डिस्काउंट और 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

डिजाइन के लिहाज से मारुति डिजायर में बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लैंप और नए 15-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। इंटीरियर में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। खास बात यह है कि यह भारत की पहली

सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ का विकल्प दिया गया है। सेप्टी के मामले में भी डिजायर ने खास पहचान बनाई है। ग्लोबल एनर्केप ने इस कार को फेमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके साथ ही इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और अन्य सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं। माइलेज की बात करें तो यह कार ग्राहकों को काफी आकर्षित करती है। मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका माइलेज 24.79 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में 25.71 किमी प्रति लीटर तक का है।

वहीं, सीएनजी मॉडल 30 किमी प्रति किलोग्राम से ज्यादा का माइलेज देता है। पावरट्रेन में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 81.58बीएचपी की पावर और 111.7 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, सीएनजी विकल्प भी उपलब्ध है। कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में मारुति डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 10.20 लाख रुपये तक जाती है।

दिवालिया कंपनी ...

6 सितंबर को चल्छेरे में विधायक के ठिकानों पर छापे में सोना, चांदी और करोड़ों की सम्पत्ति बरामद हुई थी। ईडी ने विधायक के ठिकानों से 21.43 किलो सोने के बिस्किट, 10.98 किलो सोने की परत वाली चांदी और करीब 1 किलो के गहने जब्त किए। इनकी कुल कीमत करीब 24 करोड़ रुपए बताई गई है। यह कोई पहली बरामदगी नहीं है। इससे पहले हुई छापेमारियों और जब्तियों को मिलाकर इस पूरे केस में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सम्पत्ति सामने आ चुकी है।

ईडी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि विधायक वीरेंद्र और उनके साथियों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाया। उन्होंने किंग567, राजा567, लायन567, प्ले567 और प्लेविन567 जैसी वेबसाइटें बनाकर लाखों लोगों से करोड़ों रुपए वसूलें। यह पैसा सीधा उनके खातों में नहीं डाला जाता था, बल्कि इसे पेमेंट गेटवे और फर्जी (म्यूल) बैंक खातों के जरिए इधर-उधर घुमाया जाता था, ताकि इसकी असली पहचान छुपी रहे। जांच एजेंसी के पास अब ऐसे ठोस सबूत हैं, जिनसे यह साबित हो गया है कि सारी कमाई अवैध थी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इसे सफेद दिखाने की कोशिश की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि विधायक और उसका परिवार इस काले धन का इस्तेमाल शाही जीवनशैली अपनाने में कर रहे थे। उसने कई बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं, जिनका खर्च इन्हीं पैसों से उठाया गया। साथ ही करोड़ों रुपए की लज्जरी कारें भी खरीदी गईं। ईडी ने दस्तावेजों से यह भी पाया कि एक मर्सीडीज कार एबीएच इंफ्रामैस्ट्रक्चर के नाम पर खरीदी गई थी। वहीं, एक रेंज रोवर कार की फंडिंग गुलशन खडूर नाम के व्यक्ति ने की थी। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह सारी सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित पैसों से खरीदी गई और इन्हें भी जब्ती की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। इससे पहले 4 सितंबर को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने विधायक वीरेंद्र की ईडी कस्टडी को 4 दिन और बढ़ा दिया था। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से साफ हुआ कि उसने सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों को वैध दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

नागरिकता के...

दायर कर सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। बताया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया और 1982 में हटा लिया गया जबकि 1983 में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनी थीं।



BOOK YOUR DISPLAY CLASSIFIED ADVERTISEMENTS AT
Timings : 9 am to 7 pm

Head office
SHREE SIDDHIVINAYAK PUBLICATIONS
Plot No. A-23/5 & 6 2nd Floor,
APIE, Balanagar, Hyderabad - 500 037

City office
SHREE SIDDHIVINAYAK PUBLICATIONS
4th Floor, 19 Towers (T19),
Near Bus Stand, Ranigunj,
Secunderabad - 500 003

8688868345

शुभ लाभ

महारे भाग्यनगर

दैनिक हिन्दी शुभ लाभ, हैदराबाद, गुरुवार, 11 सितंबर, 2025

शुभ लाभ

आपकी सेवा में

शुभ लाभ से जुड़ी किसी भी समस्या या सुझाव के लिए
मो. 86888 68345 पर
संपर्क करें।

महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रसेन नारी शक्ति महिला उत्सव का भव्य आयोजन



हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। अग्रवाल समाज तेलंगाना के तत्वावधान में आयोजित अग्रसेन नारी शक्ति महिला उत्सव बुधवार को अत्यंत भव्य और मनमोहक ढंग से सम्पन्न हुआ। यह आयोजन आगामी महाराजा श्री अग्रसेन महाराज जयंती महोत्सव (22 सितंबर, क्लासिक कन्वेंशन-3, शमशाबाद) की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

इस उत्सव का नेतृत्व आयोजन समिति की चेयरपर्सन रीतू अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन डिपल अग्रवाल और आरती अग्रवाल ने किया। समाज की सभी महिला शाखाओं की पदाधिकारीणियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे कार्यक्रम में ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ।

इस उत्सव की मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती

वरलक्ष्मी धीरज, तेलंगाना भाजपा राज्य महिला प्रवक्ता ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की निर्णायक श्रीमती नित्या पारीक, पूर्व जिला अध्यक्ष-महिला मोर्चा थी। कार्यक्रम में समाज की 70 महिलाएं आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों को मिला नया आयाम

व्यवसायिक स्टॉल पर समाज की महिलाएं और युवतियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। 9 महिला शाखाओं की 100 से अधिक महिलाएं मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। जिनमें-

मानसरोवर शाखा, कृष्णा सखी नचराम शाखा, ज्ञान बाग कॉलोनी शाखा, रानी सती दादी महिला शाखा, अर्ध आध्या पैराडाइज शाखा, अत्तापुर

शाखा, उत्तराखंड नारी शक्ति शाखा, गच्चीबावली महिला शाखा और शिव शक्ति महिला मोती नगर शाखा शामिल थीं।

बहू-बेटी डिजाइनर शोकेस के अंतर्गत समाज के प्रसिद्ध सात प्रतिष्ठानों द्वारा वस्त्रों का फैशन शो प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर श्रोताओं ने फोटो बूथ, लकी ड्रा, तम्बोला जैसी गतिविधियों का आनंद लिया।

यूनिवर्सल कूकवियर और पसारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपहार प्रायोजक के रूप में सहयोग दिया। कार्यक्रम में अग्रसेन जयंती की मुख्य संयोजिका एवं केंद्रीय सह-मंत्री डॉ. सीमा जैन, समाज अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता, मनीष अग्रवाल (आईपीपी), सांस्कृतिक

समिति की चेयरपर्सन रीतू अग्रवाल, डिपल अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, आरती अग्रवाल, अनु केडिया, अंजनी अग्रवाल, कपूरचंद गुप्ता, नवीन अग्रवाल, सलाहकार बट्टी विशाल बंसल, हरीश गुप्ता सहित कई गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। समाज की सभी शाखाओं की महिला पदाधिकारीणियों ने उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिससे यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध हुआ, बल्कि समाज में एकता, सहभागिता और महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश भी गया। यह महिला उत्सव न केवल अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों का हिस्सा था, बल्कि समाज में महिला नेतृत्व और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।



एक कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव एवं तेलंगाना प्रदेश भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता एन.वी. सुभाष का स्वागत करते हुए महेश बैंक के प्रोफेशनल निदेशक एवं एफटीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रमाकांत इशाणी एवं भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ नेता सतीश जाजू।

नामपल्ली पर राधे राधे ग्रुप ने किया अन्नदान



हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। राधे राधे ग्रुप हैदराबाद के तत्वावधान में बुधवार को पितृपक्ष की तृतीया तिथि के उपलक्ष्य में नामपल्ली स्थित पब्लिक गार्डन पिछर नंबर 1265-ए के पास जल्दतमद लोगों को नाश्ता (अन्नदान) कराया। नियमित अन्नदान कार्यक्रम में सतीश कुमार गुप्ता, रामप्रकाश अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, महेश अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, ई-जगन चम्पापेट, मनोज शर्मा, नंदकिशोर अग्रवाल, संजय अग्रवाल, साविता अग्रवाल, महेश गुप्ता, सुशील गुप्ता, शीतल गुप्ता, भगताराम गोयल, गोपाल गोयल, मनीष अग्रवाल आदि सदस्य उपस्थित थे।

आज का अत्पाहार

राधे राधे ग्रुप

स्व. श्री बट्टीप्रसादजी अग्रवाल
के पुण्यतिथि के अवसर पर
बट्टीप्रसाद महेशकुमार अग्रवाल, मेहदीपटनम
वितरण स्थल : भू-लक्ष्मी माता गौशाला, बेगम बाजार
SATISH KUMAR GUPTA 92465 05234
JAGAT NARAYAN AGARWAL 92465 35311
RAM PRAKASH GOEL 93910 14283
MAHESH AGARWAL 98490 98502

नीति आयोग की ईज़ ऑफ़ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर शिखर बैठक सीएसआईआर-आईआईसीटी हैदराबाद में छठी क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन

हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। नीति आयोग की ओर से ईज़ ऑफ़ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट (अनुसंधान और विकास में सुगमता) पर छठी क्षेत्रीय परामर्श बैठक बुधवार से सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद में शुरू हुई। दो दिवसीय इस बैठक में 90 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें विभिन्न संस्थानों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निदेशक शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने, बुनियादी शोध को व्यावहारिक रूप में बदलने और युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने पर विचार-विमर्श करना है। सीएसआईआर-आईआईसीटी के निदेशक डॉ. श्रीनिवास रेड्डी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के लिए विज्ञान नवाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार प्रो. विवेक कुमार सिंह ने कहा कि ये बैठकें भारत में आर एंड डी के ढांचे, नियमों और नीतियों में सुधार लाकर बाधाओं को हटाने पर केंद्रित हैं। उन्होंने



आशा व्यक्त की कि इससे भारतीय विज्ञान की वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्थिति बेहतर होगी। इस (आईएनएसए) के अध्यक्ष प्रो. आशुतोष शर्मा ने शोधकर्ताओं, प्रशासकों और नौकरशाही के बीच संबंधों को बेहतर बनाने और मजबूत

शिकायत निवारण प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने मुख्य भाषण में, सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने नीति आयोग द्वारा शुरू की गई इस परामर्श प्रक्रिया को सराहा।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाना और फेलोशिप की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है। उन्होंने विश्वास आधारित फंडिंग, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही को समय की मांग बताया। डॉ. कलैसेल्वी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की अलग-अलग कार्य प्रणालियों और समस्याओं को भी नए सुधारों में शामिल करना होगा। उन्होंने प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण में सीएसआईआर के प्रयासों की सराहना करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. सारस्वत का आभार व्यक्त किया। दो दिवसीय इस बैठक में आर एंड डी इकोसिस्टम को मजबूत करना-फंडिंग और नियामक ढांचा, ज्ञान संसाधनों तक पहुंच, संस्थागत संरचनाएं और प्रक्रियाएं और अनुप्रयुक्त एवं अनुवादात्मक अनुसंधान की ओर जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

श्री जयदेवदास खाकी जी की पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन



हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। साकेत वासी परम पूज्य श्री जयदेव दास खाकी श्रद्धांजलि अर्पित की।

जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज एक विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महंत अमृत दास खाकी के सान्निध्य में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत और भक्तगण उपस्थित रहे।

भजन संध्या में संगम पीठाधीश्वर राहुल दास, महंत बिरजू दास, महंत संजय दास, विध्याचल ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष रामशिरोमणि तिवारी और कई अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर, भजन और श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष रूप से सितार वादक विजय कुमार, श्रुति श्रीजा और सतूर वादक विजय पांचाल ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों ने जयदेव दास खाकी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।



राधे राधे ग्रुप हैदराबाद के तत्वावधान में बेगम बाजार भूदेवी माता के मंदिर के समीप स्थित गौशाला के पास पितृपक्ष की तृतीया तिथि के उपलक्ष्य में अन्नदान किया गया। इस अवसर पर जगत नारायण अग्रवाल, महेश अग्रवाल, रवि अग्रवाल, विनोद लोशनीवाल, राजेश सर (योग), अनिल भाई, गोविंद राम पचेरीया, सुनील भाई, अरुण भाई, शिव भगवान, पन्ना लाल, नीलम विजयवर्गीय, लता गोयल, मीना अग्रवाल, मनोज शर्मा, आशीष, किशन पाल आदि उपस्थित थे।

आज का अत्पाहार

राधे राधे ग्रुप

स्व. श्री रमेशचन्द्रजी गर्ग
के वतुर्थी श्राद्ध के अवसर पर
श्री दामोदरदासजी रमेशचन्द्रजी गर्ग परिवार
वितरण स्थल : मेट्रो पिछर नं. A-1265, पब्लिक गार्डन रोड
SATISH KUMAR GUPTA 92465 05234
JAGAT NARAYAN AGARWAL 92465 35311
RAM PRAKASH GOEL 93910 14283
MAHESH AGARWAL 98490 98502

छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण : वेंकटेश धोत्रे



आसिफाबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने कहा कि देश का भविष्य छात्रों से जुड़ा है और उन्हें अच्छे नागरिक बनाने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे बुधवार को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग द्वारा जिला केंद्र

स्थित एकीकृत जिला कलेक्ट्रेट भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जिला अपर कलेक्टर (स्थानीय संस्थाएं) दीपक तिवारी और आसिफाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक कोवा लक्ष्मी के साथ कलेक्टर ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण

किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कलेक्टर धोत्रे ने कहा कि शिक्षक समाज में वह कर सकते हैं जो एक अधिकारी भी नहीं कर सकता। जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद शिक्षक दूरस्थ गांवों में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं और पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार सरकारी स्कूलों

में पेयजल, बिजली, शौचालय, चारदीवारी और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने दसवीं कक्षा के वार्षिक परिणामों में प्रगति की आवश्यकता पर बल देते हुए शिक्षकों से छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

साथ ही, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले 4 पीजी प्राचार्यों, 22 स्कूल सहायकों, 14 एसजीटी, 3 कस्तूरबा गांधी विद्यालय शिक्षकों, 2 ईआरपी और 13 आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सजीवन, जिला कल्याण अधिकारी अडेपु भास्कर, जिला शिक्षा अधिकारी उदय बाबू, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के अध्यक्ष अलीबिन अहमद, मंडल शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुंबई क्राइम पुलिस ने इंसास राइफल चोरी के मामले में नौसेना कांस्टेबल और उसके भाई को किया गिरफ्तार



आसिफाबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

मुंबई क्राइम पुलिस ने नौसेना से इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 40 राउंड गोлияं चोरी करने के आरोप में भारतीय नौसेना के एक कांस्टेबल और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी, कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के पेंचिकलपेट मंडल के एलुकापल्ली गांव के निवासी हैं।

आरोपी की पहचान दुब्बाला राकेश (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। फरवरी 2025 तक उसने मुंबई स्थित नौसेना विभाग में सेवा दी,

जिसके बाद उसका तबादला केरल के एर्नाकुलम में हो गया।

6 सितंबर को राकेश मुंबई स्थित नौसेना केंद्र लौटा और अपने भाई उमेश की मदद से संतरी चौकी से एक इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 40 राउंड गोлияं चुरा लीं। चोरी के बाद दोनों अपने गृहनगर एलुकापल्ली लौट आए।

चोरी की सूचना मिलते ही मुंबई क्राइम पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और आज तड़के राकेश और उमेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए हथियार और गोлияं बरामद कर ली हैं। जिला पुलिस

अधीक्षक (एसपी) कांतिला पाटिल, आईपीएस ने इस ऑपरेशन में मुंबई क्राइम पुलिस के साथ समन्वय और सहयोग के लिए कागजनगर ग्रामीण सीआई कुमारस्वामी और पेंचिकलपेट एसआई अनिल कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। एसपी पाटिल ने इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर अपराध बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील भी की।

गुरुकुल पाठशाला में मंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

वॉलीबॉल, खोखो और कबड्डी में दिखेगा खिलाड़ियों का दमखम



मदनूर, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

मंडल केंद्र स्थित बालक गुरुकुल विद्यालय में बुधवार को मंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ।

व्यायाम शिक्षकों ने बताया कि प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, खोखो और कबड्डी के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। इन खेलों में विजेता टीमों आगे क्षेत्रीय स्तर पर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी।

उद्घाटन समारोह में हनुमान स्वामी, कृष्णा पटेल, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। खिलाड़ियों में उत्साह और जोश देखने लायक था।

केजीबीवी नासपुर स्कूल में आत्महत्या रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने की पहल

मंचेरियाल, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

वैश्विक आत्महत्या रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. अनीता के नेतृत्व में केजीबीवी नासपुर स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

डॉ. अनीता ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केंद्रों में आत्महत्या रोकथाम से जुड़ी सावधानियों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए परिवार के सदस्यों से खुलकर चर्चा करें,



जिससे मानसिक तनाव कम होगा और समस्याओं का समाधान संभव होगा। कार्यक्रम में मौजूद मनोचिकित्सक ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि विचारों और

समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से छोटी-छोटी परेशानियां भी आसानी से हल हो सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्महत्या का प्रयास करना,

आत्महत्या करना या इसके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि यह गंभीर मानसिक संकट की ओर ले जाता है। सकारात्मक सोच, प्रेरणा, कड़ी मेहनत, दृढ़ता

और लक्ष्य निर्धारण से ऐसे खतरों से बचा जा सकता है।

डॉ. अनीता ने जोर देकर कहा कि बच्चों और अभिभावकों दोनों को मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। इस अवसर पर डॉ. अप्पाला प्रसाद (कार्यक्रम अधिकारी), डॉ. सुनील (मनोचिकित्सक), लिंगारेड्डी पद्मा, नानदेव, स्कूल की प्रधानाध्यापिका मौनिका, छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण और बुक्का वेंकटेश्वरलु (जिला मास मीडिया अधिकारी) उपस्थित रहे।

चकाली ऐलम्मा की पुण्यतिथि पर जिला कलेक्टर ने विकास के लिए प्रेरणा लेने का किया आह्वान

आसिफाबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

आसिफाबाद जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने कहा कि वीरनारी चकाली ऐलम्मा के साहस और संघर्ष से प्रेरणा लेकर जिले के विकास के लिए सभी को समन्वित रूप से कार्य करना चाहिए। बुधवार को आसिफाबाद जिला केंद्र में स्थित एकीकृत जिला कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तत्वावधान में चकाली ऐलम्मा की पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आसिफाबाद निर्वाचन क्षेत्र की विधायक कोवा लक्ष्मी, राजका संगम और पिछड़ा वर्ग कल्याण संघों के



प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में चकाली ऐलम्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने अपने संबोधन में कहा कि चकाली ऐलम्मा एक ऐसी साहसी

महिला थीं, जिन्होंने तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष की पहली पीढ़ी में भूमि, आजीविका और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने जमींदारों और राजकारों के खिलाफ न केवल डटकर मुकाबला किया,

बल्कि अपने साहस से समाज को एक नई दिशा दिखाई। उनकी वीरता और समर्पण आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है। कलेक्टर ने घोषणा की कि चकाली ऐलम्मा की स्मृति में जिला केंद्र में एक सामुदायिक

भवन और उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे ऐलम्मा के आदर्शों को अपनाकर जिले के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करें। इस अवसर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सजीवन, जिला कल्याण अधिकारी भास्कर, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के अध्यक्ष अलीबिन अहमद, जिला रजाक समिति के अध्यक्ष कदथा मल्लैया, संघ के प्रतिनिधि कोंडापल्ली भूमेया, राजेंद्र, बी.सी. कल्याण समिति के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कर्ज के बोझ से टूटे परिवार की त्रासदी – नारंजा नहर में कूदकर चार की मौत, दो की बची जान



भालकी (बीदर), 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

बीदर जिले के भालकी तालुका के महर गांव के पास स्थित नारंजा डैम की बाईं ओर बहने वाली नहर में मंगलवार को एक ही परिवार के छह सदस्यों ने कर्ज के बोझ से तंग आकर

छलांग लगा दी। इस दर्दनाक घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि मां और एक बच्चे को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। घटना के समय मौजूद ग्रामीणों ने सभाबाई और एक सात वर्षीय बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

मृतकों में शिवमूर्ति मारुति (45), श्रीकांत मारुति (8), अधिक (4) और राकेश (7 माह) शामिल हैं। नहर में तेज बहाव के कारण चारों बहकर आगे चले गए और उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बीदर जिले के पालकमंत्री ईश्वर खंडेर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को विस्तृत जांच करने और पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हरसंभव मदद देने के निर्देश दिए। मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम भालकी के सरकारी अस्पताल में किया गया और शाम को परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले की रिपोर्ट भालकी तालुका के धनूरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

अटल टिकरिंग लैब्स के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं बूट कैंप सम्पन्न



छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित

आसिफाबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

अटल टिकरिंग लैब्स के तत्वावधान में वाग्देवी महाविद्यालय के इनोवेटिव एम्बेसडर महाराणु यशवंत द्वारा श्री

सरस्वती शिशु मंदिर (अंग्रेजी माध्यम), बापूनगर में दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं बूट कैंप का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के साथ वाग्देवी महाविद्यालय और सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय आधिकारिक रूप से अटल टिकरिंग लैब्स से संबद्ध हो गए। पहले दिन छात्रों को रचनात्मक कौशल विकसित करने, विचारों को आकार देने, नए नवाचारों और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग के तरीकों से अवगत कराया गया। इसके बाद छात्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उनका विश्लेषण किया गया, त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारने के सुझाव दिए गए। मेंटोरशिप सत्र में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। छात्रों के प्रोजेक्ट्स को शिक्षकों से जोड़ा गया ताकि उन्हें आगे विकसित किया जा सके।

दूसरे दिन छात्रों के अभिनव विचारों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें 15 छात्रों ने भाग लिया।

राठौड़ रविंदर जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित

आसिफाबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

कुमरम भीम आसिफाबाद जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को गुरु पूजा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को उनकी असाधारण सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। जिला प्रशासनिक अधिकारी दीपक तिवारी और स्थानीय विधायक कोवा लक्ष्मी ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में राठौड़ रविंदर भी शामिल थे, जिन्हें जनता ने उत्साहपूर्वक सम्मानित किया। राठौड़ रविंदर ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला स्तर पर पहली



बार आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में पुरस्कार के लिए चयन होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनकी जिम्मेदारियों को कार्य करने में अवसर मिलना उनके लिए गौरव का विषय है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाएं, जैसे पीएम जन मन और पीएम जूगा,

जाति कल्याण विभाग में विशेष सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (एससीआरपी) के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाते हुए स्कूलों और सामाजिक कार्यक्रमों में कार्य करने में अवसर मिलना उनके लिए गौरव का विषय है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाएं, जैसे पीएम जन मन और पीएम जूगा,

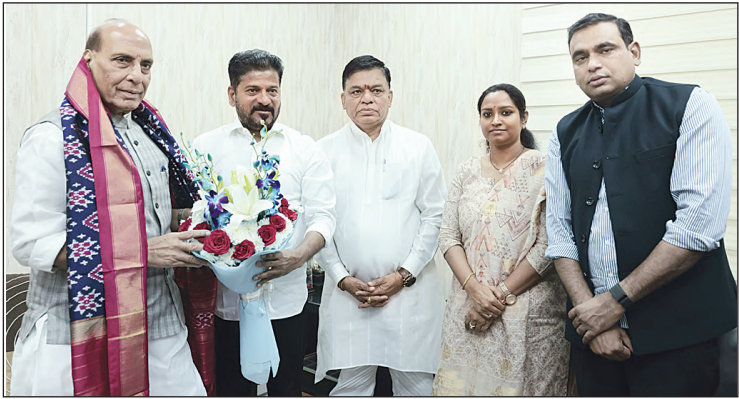
आदिवासी समुदाय तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में जिले के अन्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों, शिक्षक संघ के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने गांधी सरोवर परियोजना के लिए रक्षा भूमि हस्तांतरण की मांग की

नई दिल्ली/हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और हैदराबाद में 98.20 एकड़ रक्षा भूमि को प्रतिष्ठित गांधी सरोवर परियोजना के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। बैठक में, मुख्यमंत्री ने मूसी और ईसा नदियों के संगम पर गांधी एकता मंडल स्थापित करने की राज्य की योजना के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांधी सरोवर परियोजना राष्ट्रीय एकता और महात्मा गांधी के शाश्वत आदर्शों का स्थायी प्रतीक बनेगी। पिछले साल नवंबर में राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में, मुख्यमंत्री ने बापू घाट पर इस परियोजना के विकास के लिए 222.27 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने की मांग की थी।

राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि बापू घाट, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं, को



ग्रीनफील्ड सड़क नेटवर्क के लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात

मंगलवार शाम को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी को अमरावती के रास्ते बंडारू बंदरगाह से जोड़ने वाले 12-लेन ग्रीनफील्ड सड़क नेटवर्क को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि आंध्र

प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानियों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड सड़क नेटवर्क के विकास का वादा किया गया था। चूंकि तेलंगाना में कोई बंदरगाह नहीं है, मुख्यमंत्री ने हैदराबाद से बंदरगाह तक माल के सीधे परिवहन की सुविधा के लिए इस सड़क को मंजूरी देने की अपील की। इस प्रस्तावित

विकसित किया जाए। इस भूमि हस्तांतरण का उद्देश्य गांधी दर्शन के वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए एक केंद्र विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने परियोजना के विभिन्न घटकों, जैसे ज्ञान केंद्र, ध्यान ग्राम, हथकरघा संवर्धन केंद्र, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, भूदृश्य, शांति प्रतिमा और संग्रहालय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बापू घाट पर महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

सड़क का 118 किलोमीटर हिस्सा तेलंगाना में और शेष आंध्र प्रदेश में होगा। गडकरी ने आश्वासन दिया कि इस परियोजना का अध्ययन करने के लिए एक आधिकारिक टीम हैदराबाद भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 सितंबर को हैदराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के साथ समीक्षा बैठक होगी।

क्रांतिकारी योद्धा चकाली ऐलम्मा को श्रद्धांजलि



नई दिल्ली/हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की क्रांतिकारी योद्धा चित्पाला ऐलम्मा, जिन्हें चकाली ऐलम्मा के नाम से भी जाना जाता है, की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली दौरे के दौरान, उन्होंने ऐलम्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके वीरतापूर्ण संघर्ष को याद

किया। मुख्यमंत्री ने ऐलम्मा को उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बताया, जिन्होंने लगभग 80 साल पहले तेलंगाना में सामंती अहंकार और अधिनायकवाद के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना थलू की प्रतिमा को सम्मका, सरका और चकाली ऐलम्मा जैसी प्रख्यात महिलाओं से प्रेरणा लेकर डिजाइन

किया गया है। इस अवसर पर सांसद पी. बलराम नाइक और किरण कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भी ऐलम्मा को श्रद्धांजलि दी, यह कहते हुए कि उनकी जमीन, आजीविका और जबरन मजदूरी से मुक्ति की लड़ाई ने तेलंगाना के लोगों की लचीलापन और जुझारूपन को दुनिया के सामने पेश किया। उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा, वह प्रतिरोध की सच्ची मिसाल थी, जिन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और विशेषकर महिलाओं की पीढ़ियों को सम्मान और आत्मसम्मान के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत हमें समानता और न्याय के लिए साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलापन की आवश्यकता को याद दिलाती है।

नेपाल में तनाव के बीच तेलंगाना सरकार ने हेल्पलाइन स्थापित की

नई दिल्ली/हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। नेपाल में व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देश पर नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब तक कोई तेलंगाना नागरिक नेपाल में परेशानी में नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय और काठमांडू के भारतीय दूतावास के साथ मिलकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

नेपाल में फंसे नागरिकों के परिवार इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:- सुश्री वंदना, निजी सचिव और रजिस्टर्ड कमिश्नर की संपर्क प्रमुख: +91 9871999044

जी. रश्मि नायक, संपर्क अधिकारी: +91 9643723157
सीएच. चक्रवर्ती, जनसंपर्क अधिकारी: +91 9949351270
सरकार ने नागरिकों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने और झूठे प्रचार से बचने का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नेपाल में तेलंगाना के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

डाकिया द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद वकील को जीवित साबित करना पड़ा

हैदराबाद, 10 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। डुंडीगल गांव में एक अजीबोगरीब घटना में, स्थानीय डाकिया द्वारा गलती से मृत घोषित किए जाने के बाद वकील अजय गोड़ (35) को यह साबित करना पड़ा कि वह जीवित हैं। 30 अगस्त को एक चिटफंड कंपनी ने अजय को स्पीड पोस्ट के जरिए अनुबंध पत्र भेजे। डाकिया ने बिना पुष्टि किए लिफाफे पर



उनकी मृत्यु दर्ज कर वापस भेज दिया। 18 सितंबर को कंपनी के फोन कॉल से अजय को इस वृत्ति का पता चला। डाकिया ने दावा किया कि पड़ोसियों ने उनकी मृत्यु की जानकारी दी थी। अजय ने डुंडीगल पुलिस और डाक अधिकारियों में शिकायत दर्ज करने की इच्छा जताई, इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद स्थिति बताते हुए।



श्री हैदराबाद सिकंदराबाद लोहाणा महाजन लव फॉर काऊ फाउंडेशन एवं हैदराबाद सुंदरकांड मंडल के संयुक्त तत्वावधान में



श्रीमद् भागवत पारायण

रविवार दि. 14 सितम्बर से शनिवार दि. 20 सितम्बर 2025

समय : प्रतिदिन दोपहर 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

स्थान : श्री जलाराम बापा मंदिर, बडीचावडी, हैदराबाद

पोथी यात्रा : रविवार दि. 14 सितम्बर 2025 प्रातः 10.11 बजे 108 कलशों के साथ श्री जलाराम मंदिर से प्रारंभ होकर पुनः श्री जलाराम मंदिर बडीचावडी पहुंचेगी।

प.पु. डॉ. रेजिनी महाराज की प्रेरणा से गत 37 वर्षों से जलाराम मंदिर में राम धून के साथ प्रतिदिन अन्न प्रसाद का वितरण किया जा रहा है।



श्रीमद् भागवत पारायण में पोथी यजमान, प्रतिदिन यजमान, सहयजमान एवं मुख्य यजमान आदि विभिन्न रूप से सहयोग करने के इच्छुक पहले आओ पहले पाओ के रूप में भाग ले सकते हैं।
For details contact: Rajesh Ramani-7093621683, Jasmat Patel-7288047779, Meenaben Thakkar-9395524488

पितृमास में अपने पितृओं की आत्म कल्याण हेतु श्रीमद् भगवत पारायण में पाटला पुजा अनुदान मात्र रु. 21 हजार

Always Use Cow Milk Cow Ghee
Jasmat Nanjibhai Patel Ph : 72880 47779
Ridesh Ramesh Jagirdar Ph : 98499 88999
Ranjana Manish Shah Ph : 98853 59009
Save Animals Save Nation - Donate Generously for Gaushalas

चौथा/उठाला

श्री प्रवीण कपूर जी

20/08/1956 - 08/09/2025

चौथा एवं उठाला

आज, गुरुवार दि. 11 सितंबर 2025 को

मध्याह्न 3:00 से शाम 4:00 बजे तक

स्थान : आला लिबर्टी, रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद पर होगा

:- शोकाकुल :-

मधु कपूर (पत्नी)

कुसुम आनंद
सुमन कुमार
कंचन-सीएम कपूर
मन मोहन कपूर
प्रभा-सुनील भंडारी

सामाक्षी कपूर
जागृति कपूर
अदिति-अंकुर सेठ
रौनक-रेया कपूर
ध्रुव-प्रिया कपूर
विजय-पूनम चौबे

सुनील कुमार मेहरा
सीता-राजेश भसीन
विवेक मेहरा (बोंगी)
दमन-चरणजीत साहनी
विपन-अंजू सेठ